



सत्यमेव जयते

पंचायती राज संस्थाओं पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

विषय सूची	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		(iii)
अध्याय—I		
पंचायती राज संस्थाओं पर एक विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
संगठनात्मक ढांचा	1.2	2
पंचायती राज संस्थाओं के वित्त व्यवस्था पर डाटा बेस	1.3	3
राजस्व का स्रोत	1.4	3
निधियों का उपभोग	1.5	6
समग्र वित्तीय स्थिति	1.6	8
जिला नियोजन समितियां	1.7	9
बजट तैयार किया जाना और बजट की प्रक्रिया	1.8	9
लेखांकन व्यवस्थायें	1.9	10
सम्प्रेक्षा प्रबन्ध	1.10	11
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को तकनीकी मार्गदर्शक एवं पर्यवेक्षण के लिए सम्प्रेक्षा को सौंपे जाने की स्थिति	1.11	11
अन्य बिन्दु	1.12	12
निष्कर्ष	1.13	12
अध्याय—II		
निष्पादन लेखा परीक्षा		
पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान राशि की प्राप्ति तथा उसके उपभोग की निष्पादन लेखा परीक्षा		
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
कार्यकारी सार	2	13
परिचयात्मक	2.1	14
संगठनात्मक ढांचा	2.2	15
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.3	15
लेखापरीक्षा का अभिप्राय एवं कार्य प्रणाली	2.4	16
नियोजन	2.5	16

वित्तीय प्रबन्धन	2.6	20
क्रियान्वयन	2.7	23
आन्तरिक नियन्त्रण एवं अनुश्रवण	2.8	29
निष्कर्ष	2.9	30
संस्तुतियां	2.10	31
अध्याय—III		
लेन देनों की लेखा परीक्षा	3	32
रायल्टी का अनियमित भुगतान	3.1	32
अधोमानक कार्य पर निष्फल व्यय	3.2	33
परिहार्य व्यय	3.3	34
राजस्व की हानि	3.4	34
परिशिष्टियां		
विवरण	परिशिष्ट संख्या	पृष्ठ संख्या
जिला पंचायत में कर संग्रह में अवशेष (2008–09)	1.1	36
रोकड़ अवशेष का मिलान न किया जाना	1.2	37
जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में स्वीकृत एवं अवमुक्त का विवरण	2.1	38
विलम्ब (15 दिन से अधिक) एवं दण्डात्मक ब्याज की धनराशि @11.75% प्रति वर्ष	2.2	39
आपूर्तिकर्ताओं को बिना आयकर कटौती के भुगतान का विवरण	3.1	40

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा यथा संस्तुत एवं राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2001 में सौंपे जाने के उपरान्त भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लेखे के समुचित अनुरक्षण और उनकी लेखा परीक्षा पर तकनीकी दिशा निर्देशन और पर्यवेक्षण (टी जी एस) के निर्बंधनों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के लेखापरीक्षण के फलस्वरूप, वर्ष 2009—10 में पायी गयी मुख्य आपत्तियों का एकीकरण है।

इस प्रतिवेदन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज संस्थाओं की कार्य शैली का विहंगावलोकन तथा प्रशासकीय विभागों का ध्यानाकर्षण एवं आवश्यकतानुसार समुचित कार्यवाही एवं सुधार करना है।

वर्ष 2009—10 की अवधि में 3,487 पंचायती राज संस्थाओं की लेखाओं की नमूना जांच में संज्ञान में आये प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है।

अध्याय-I

पंचायती राज संस्थाओं का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

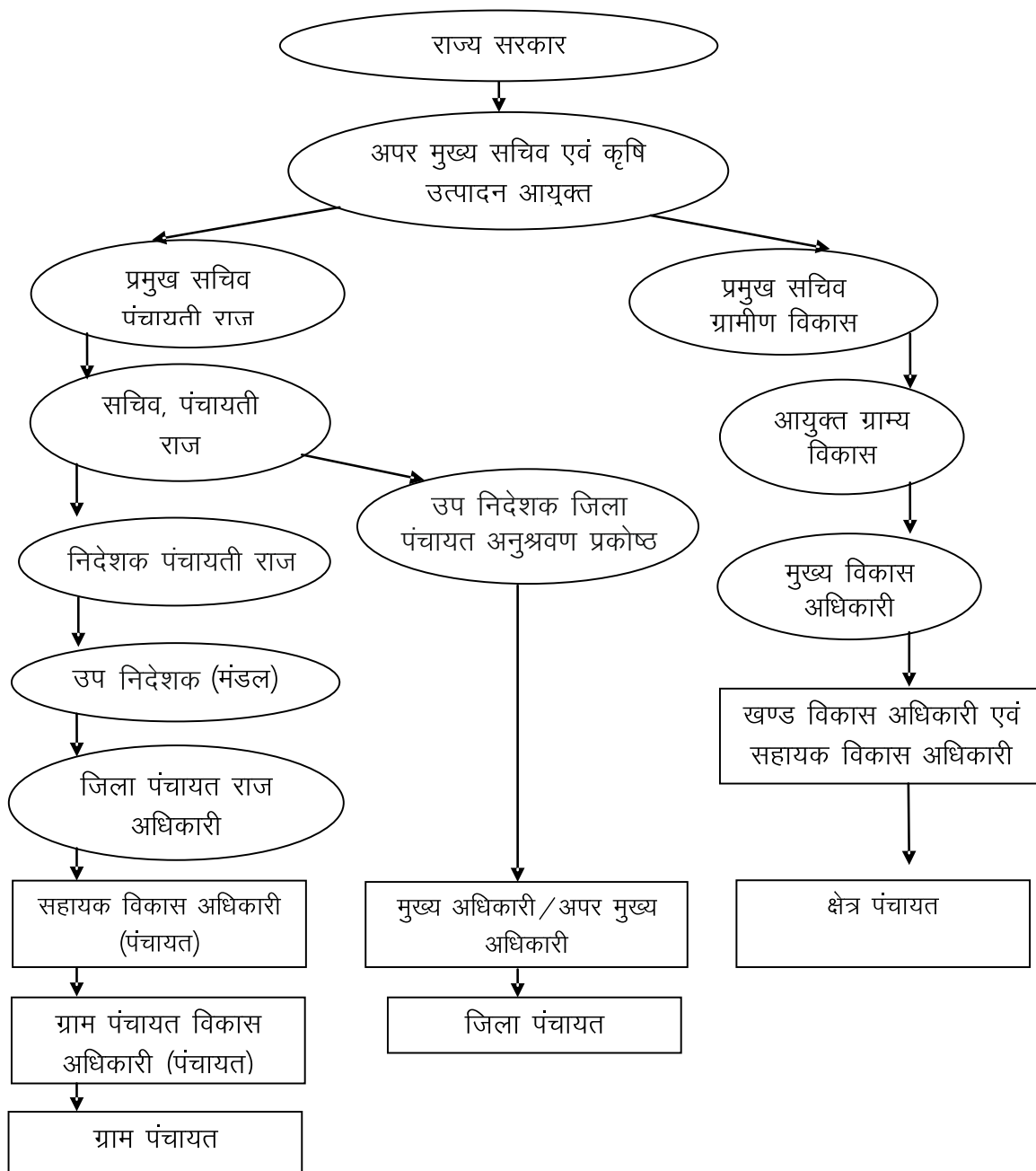
तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को दृष्टिगत रखते हुये चुनी गयी निकायों की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हेतु उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 को 1994 में संशोधित किया गया। संशोधित अधिनियम ग्रामीण स्वायत्तशासी निकायों, यथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत एवं जिला स्तर पर जिला पंचायत, की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण का वर्णन करता है जो उस समय तक राज्य सरकार में निहित थे। पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था का उद्देश्य सामान्य जन की भागीदारी में वृद्धि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन था। समग्र पर्यवेक्षण समन्वय, नियोजन एवं विकास योजनाओं का क्रियान्वयन जिला पंचायत में निहित था। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की सम्पूर्ण ग्रामीण आबादी 13.71 करोड़ थी। मार्च 2010 के अन्त में राज्य में 72 जिला पंचायतें¹ 821 क्षेत्र पंचायतें एवं 51,914 ग्राम पंचायतें थी।

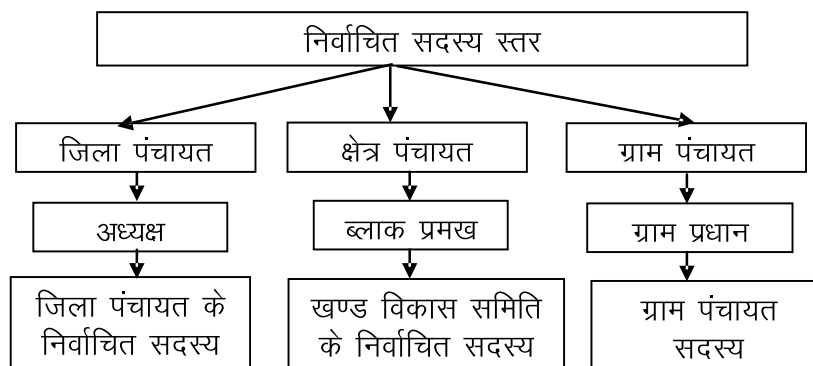
इन पंचायती राज संस्थाओं के चयनित निकायों का विगत चुनाव अक्टूबर-नवम्बर 2010 में हुआ था जिसमें ग्राम पंचायतों के लिए 51,914 ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के लिए 821 ब्लॉक प्रमुखों एवं जिला पंचायतों के लिए 72 अध्यक्षों का चुनाव किया गया था।

¹जिला पंचायत छत्रपति शाहूजी महाराज नगर वर्ष 2010 में सृजित किया गया।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

पंचायती राज संस्थाओं का त्रिस्तरीय प्रशासनिक नियंत्रण निम्नवत है—





1.3 पंचायती राज संस्थाओं के वित्त व्यवस्था पर डाटा बेस

ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार भारत सरकार स्तर पर राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के निष्पादन की तुलना को सुविधाजनक बनाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं की आर्थिक व्यवस्था पर एक डाटाबेस जिला स्तर, राज्य स्तर एवं भारत सरकार स्तर पर विकसित किया जाना था, जिसे कम्प्यूटरीकृत कर अति छोटी इकाईयों तक आविधिक रूप से सम्बद्ध करते हुए पहुँच योग्य बनाना था।

इसके अनुक्रम में ₹ 104.56 करोड़² स्वीकृत किया गया था और जिला पंचायत, लखनऊ के बैयक्तिक लेजर खाते में संरक्षित किया गया था। इसमें से ₹ 42.07 करोड़ सरकारी लेखों में अन्तर्गत (नवम्बर 2009) कर दिया गया था, ₹ तीन लाख कार्यक्षेत्र के परीक्षण हेतु आई आई टी को भुगतान (मार्च 2010) कर दिया गया था कार्य क्षेत्र की जांच आई आई टी कानपुर द्वारा की गयी और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित (मार्च 2010) कर दिया गया था, ₹ 62.37 करोड़ पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं के रख रखाव हेतु पंचायती राज संस्थाओं को अन्तर्गत (जनवरी 2011) किया गया था एवं शेष ₹ नौ लाख बैयक्तिक लेजर खाता में अवशेष पड़ा हुआ था। डाटा बेस तैयार नहीं किये जाने के कारण दूसरे राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं से तुलना के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का निष्पादन करने से सरकार वंचित रही।

1.4 राजस्व का स्रोत

1.4.1 राजस्व का प्रवाह

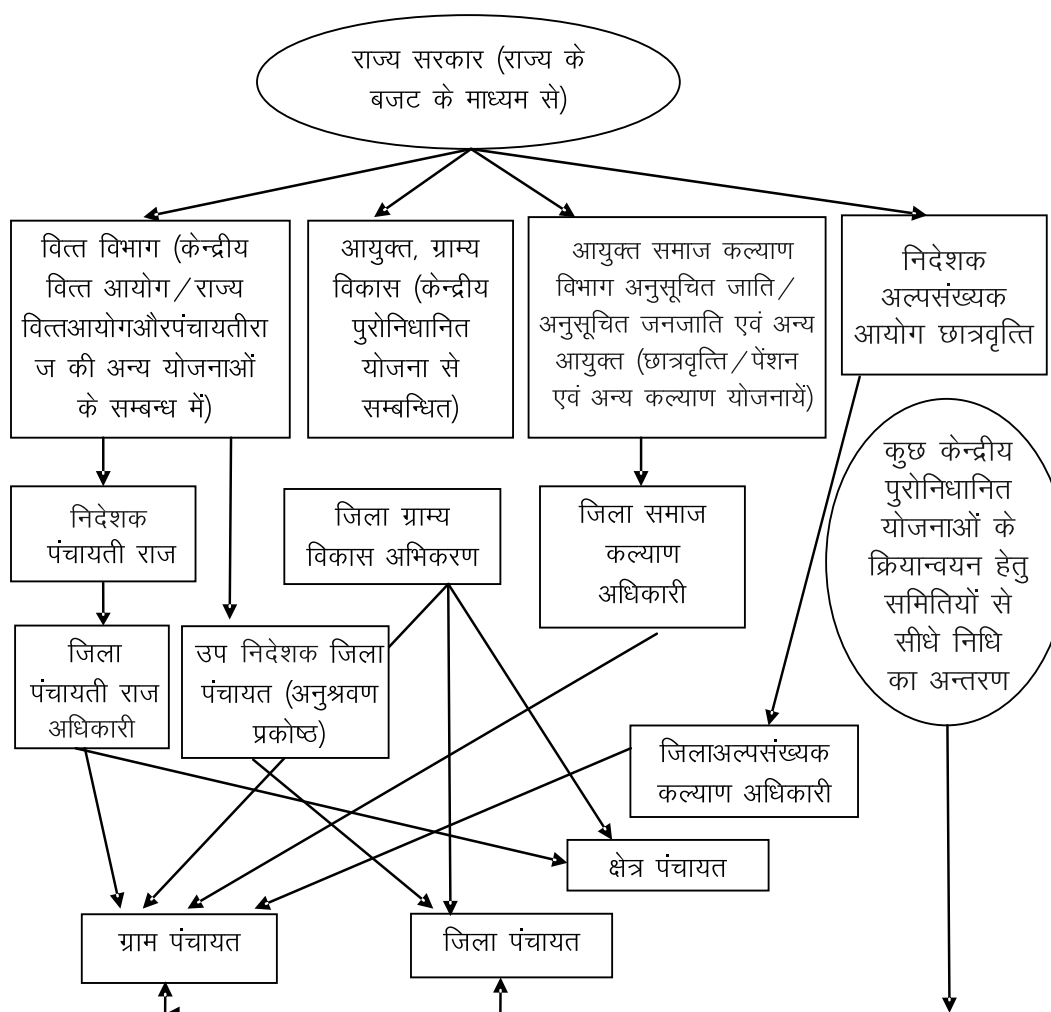
पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से बारहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग ने राज्य सरकार से उन्हें अनुदान अवमुक्त करने की अनुशंसा की थी। सभी तरह से पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व के स्रोत निम्नवत हैं—

² 11वाँ वित्त ₹ 21.04 करोड़ (2000-01) ₹ 21.03 करोड़ (2001-02) तथा 12 वाँ वित्त आयोग ₹ 33.64 करोड़ (2006-07) एवं ₹ 28.85 करोड़ (2007-08)।

- बारहवां वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन समनुदेशित अनुदान ;
- द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य के शुद्ध कर राजस्व के शुद्ध आगमों का पांच प्रतिशत अंश,
- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के निष्पादन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के माध्यम से प्राप्त अनुदान,
- पंचायती राज संस्थाओं को अन्तर्गत कार्यों के लिए विभागों से प्राप्त निधियां,
- निजी स्रोतों जैसे करो, किराये, शुल्कों इत्यादि से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अर्जित राजस्व ।

1.4.2 निधि प्रवाह तालिका

निजी स्रोतों से इतरकेन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अधिकांश केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थाओं को निधियों का प्रवाह होता है। पंचायती राज संस्थाओं को आधारभूत स्तर पर निधियों का प्रवाह निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है:-



1.4.3 कुल प्राप्तियां

2005-10 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को बारहवें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्राप्त कुल अनुदान, केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान और निजी स्रोतों से प्राप्त राजस्व की स्थिति तालिका-1 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1— पंचायती राज संस्थाओं की कुल प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बारहवां वित्त	राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनायें	निजी स्रोत	योग
2005-06	585.60	816.94	1,949.96	80.95	3,433.45
2006-07	585.60	1,169.05	1,698.37	73.90	3,526.92
2007-08	585.60	1,567.77	3,340.80	90.75	5,584.92
2008-09	587.28	1,281.68	8,679.89	91.80	10,640.65
2009-10	585.60	1,262.07	12,119.67	103.73	14,071.07
योग	2,929.68	6,097.51	27,788.69	441.13	37,257.01

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज लखनऊ, उप निदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ लखनऊ, आयुक्त, ग्राम्य विकास लखनऊ)

वर्ष 2005-10 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि का क्रम था। केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं में अधिक वृद्धि हुयी थी।

1.4.4 राज्य वित्त आयोग अनुदान का हस्तान्तरण

द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने संस्तुति की थी कि कुल कर राजस्व के शुद्ध आगमों का पांच प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित होना चाहिए। निधियों का हस्तान्तरण एवं सरकार द्वारा अवमुक्त वास्तविक निधियां (2005-2010) तालिका-2 में दर्शायी गयी है।

तालिका-2: शुद्ध आगम तथा पंचायती राज संस्थाओं को निधियों का हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य सरकार की कर राजस्व के शुद्ध आगम	निधियाँ हस्तान्तरण की जानी थी	वास्तव में हस्तान्तरित निधियां	कमी / आधिक्य	प्रतिशत
2005-06	18,858	943	817	(-) 126	(-) 13
2006-07	22,998	1,150	1,169	(+) 019	(+) 02
2007-08	24,959	1,248	1,568	(+) 320	(+) 26
2008-09	28,659	1,433	1,282	(-) 151	(-) 11
2009-10	33,878	1,694	1,262	(-) 432	(-) 26
योग	129,352	6,468	6,098	(-) 370	(-) 6

(स्रोत: वित्त लेखा एवं निदेशक पंचायती राज लखनऊ, उपनिदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ लखनऊ, आयुक्त ग्राम्य विकास लखनऊ)

यद्यपि 2005-10 के दौरान हस्तान्तरण में कुल ₹370 करोड़ की कमी थी, अधिकतम कमी वर्ष 2009-10 के दौरान पायी गयी जब ₹1,694 करोड़ के सापेक्ष केवल ₹1,262 करोड़

हस्तान्तरित किये गये थे (26 प्रतिशत कम)। इससे पंचायती राज संस्थायें अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी गतिविधियों की योजना बनाने तथा उन्हें लागू करने से वंचित रहीं।

1.5 निधियों का उपभोग

1.5.1 बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों का उपभोग

2005–2010 के दौरान बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध, उपभोग एवं अनुपभोग निधियों की स्थिति तालिका-3 में दर्शायी गयी है।

तालिका-3: बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त निधियों का उपभोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उपलब्ध निधियां	उपभोग निधियां	अनुपभोग निधियां
2005–06	585.60	585.02	0.58
2006–07	585.60	551.96	33.64
2007–08	585.60	556.52	29.08
2008–09	587.28	587.10	0.18
2009–10	585.60	580.25	5.35
योग	2,929.68	2,860.85	68.83

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, लखनऊ)

वर्ष 2009–10 के दौरान निदेशालय स्तर पर कोषागार से अनाहरण के कारण ₹ 5.35 करोड़ सरकारी लेखे को व्यपगत हो गये। विश्लेषण से आगे ज्ञात हुआ कि उपभोग की हुयी निधियों के आंकड़े वास्तविक नहीं थे क्योंकि अवमुक्त निधियों को ही उपभोग मान लिया गया था।

1.5.2 राज्य वित्त आयोग के अनुदान का उपभोग

2005–10 के दौरान राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध, उपभोग एवं अनुपभोग किये गये अनुदान की स्थिति तालिका 4 में दर्शायी गयी है—

तालिका 4: राज्य वित्त आयोग अनुदान का उपभोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त निधियां	कुल उपलब्ध निधियां	उपभोग निधियां (प्रतिशत)	अनुपभोग निधियां (प्रतिशत)
2005–06	61.11	816.94	878.05	504.36 (57)	373.69 (43)
2006–07	373.69	1,169.05	1,542.74	724.01 (47)	818.73 (53)
2007–08	818.73	1,567.77	2,386.50	1,065.30 (45)	1,321.20 (55)
2008–09	1,321.20	1,281.68	2,602.88	1,280.71 (49)	1,322.17 (51)
2009–10	1,322.17	1,262.07	2,584.24	1,168.01 (45)	1,416.23 (55)

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज, उपनिदेशक, जिला पंचायत, लखनऊ)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत राज संस्थाओं द्वारा निधियों के उपभोग की गति धीमी थी क्योंकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में बड़ी धनराशि बिना व्यय के पड़ी थी। स्पष्ट रूप से जनता मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, जलापूर्ति एवं सफाई आदि विकास सम्बन्धी गतिविधियों के लाभों से वंचित रही।

1.5.3 केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुदान

पंचायती राज संस्थाएँ केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं की प्रारम्भिक स्तर पर कार्यदायी संस्थाएँ हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकार इसके लिए निधियाँ अवमुक्त करती हैं। केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 2006-10 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राप्त अनुदानों की स्थिति तालिका 5 में दर्शायी गयी है—

तालिका-5: केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनुदान

केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के नाम एवं अवधि	प्राप्त अनुदान			अवमुक्त अनुदान
	केन्द्र	राज्य	योग	
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (2006-08)	873.55	286.66	1,160.21	1,160.21
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (2006-10)	1,246.24	419.01	1,665.25	1,665.25
इन्दिरा आवास योजना (2006-10)	2,873.08	944.93	3,818.01	3,818.01
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (2006-10)	10,753.92	1,183.26	11,937.18	11,937.18
प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (2008-10)	4,486.95	—	4,486.95	4,486.95
ग्रामीण पेयजल योजना (2008-10)	1,493.90	1,078.96	2,572.86	2,572.86
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (2008-10)	119.44	32.75	152.19	152.19
बायो गैस (2008-10)	1.32	—	1.32	1.32
योग	21,848.40	3,945.57	25,793.97	25,793.97

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास लखनऊ)

1.5.4 निजी स्रोतों से प्राप्त राजस्व

पंचायती राज संस्थाएँ जनता से कर, किराया, शुल्क आदि लगाकर राजस्व प्राप्त करती हैं तदनुसार सरकार ने उनके लिए राजस्व वसूली का लक्ष्य 2007-10 निर्धारित किया था। तालिका-6, 2007-10 के दौरान निर्धारित लक्ष्य एवं वसूल किये गये राजस्व को प्रदर्शित करती है।

तालिका-6: निजी स्रोतों से प्राप्त राजस्व

(₹ करोड़ में)

पंचायती राज संस्थाओं के नाम (संख्या कोष्ठक में)	2007-08		2008-09		2009-10	
	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)
जिला पंचायत (71)	83.42	86.37 (104)	93.86	88.22 (94)	103.26	100.60 (97)
ग्राम पंचायतें (51,914)	4.88	4.39 (90)	4.53	3.58 (79)	4.42	3.13 (71)
योग	88.30	90.76 (103)	98.39	91.80 (93)	107.68	103.73 (96)

(स्रोत: निदेशक, पंचायती राज एवं उपनिदेशक, जिला पंचायत लखनऊ)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्व की वसूली में कमी 29 प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत के बीच रही।

अग्रेतर, 29 जिला पंचायतों ने 2008-09 में किरायेदारों, लाइसेंसधारियों एवं ठेकेदारों आदि से किरायें, लाइसेंस शुल्क आदि के अवशेष ₹ 36.17 करोड़ को शामिल करते हुए ₹ 74.96 करोड़ की मांग प्रस्तुत की (परिशिष्ट 1.1) इसमें से ₹ 37.25 करोड़ की वसूली हुई एवं शेष ₹ 37.71 करोड़ अभी तक वसूली हेतु लम्बित थे।

1.6 समग्र वित्तीय स्थिति

जैसा कि पूर्व वर्ती प्रस्तर 1.3 और उत्तर वर्ती प्रस्तर 1.10 में वर्णित है, न तो पंचायती राज संस्थाओं के वित्त व्यवस्था पर डाटाबेस की संरचना की गयी, न ही लेखे तैयार किये गये। परिणामस्वरूप, प्रारम्भिक अवशेष, प्राप्तियां, व्यय एवं अन्तिम अवशेष दर्शाते हुए पंचायती राज संस्थाओं की समग्र वित्तीय स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

वर्ष 2009-10 में 3,487 पंचायती राज संस्थाओं के लेखाभिलेखों की लेखापरीक्षण किया गया। इन संस्थाओं की विगत तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति तालिका-7 में दर्शायी गयी है।

तालिका-7: विगत तीन वर्षों में लेखा परीक्षित इकाईयों की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पंचायती राज संस्थाओं की संख्या जिनकी जांच की गयी	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त निधियां	कुल प्राप्त निधियां	व्यय (कोष्ठक में) प्रतिशत	अन्तिम अवशेष
जिला पंचायत						
2006-07	52	338.56	476.91	815.47	497.80(61)	317.67
2007-08	52	319.41	589.80	909.21	484.00(53)	425.21
2008-09	55	439.04	993.15	1,432.19	1,022.87(71)	409.32

क्षेत्र पंचायतें						
2006—07	139	51.19	160.57	211.76	151.53(72)	60.23
2007—08	130	53.33	282.39	335.72	274.59(82)	61.13
2008—09	300 ³	156.36	532.09	688.45	503.09(73)	185.36
ग्राम पंचायतें						
2006—07	2,430	39.18	135.36	174.54	132.32(76)	42.22
2007—08	4,525	87.28	376.92	464.20	346.73(75)	117.47
2008—09	3,003 ⁴	71.85	363.89	435.74	307.84(71)	127.90

(स्रोत: लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन)

तालिका का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं ने निधियों का कम उपभोग किया। सर्वाधिक अवरोधन जिला पंचायतों में था जहां मार्च 2009 के अन्त में ₹ 409.32 करोड़ अनुपयोगित पड़ा था। परिणामस्वरूप निधियों का संचयन जारी रहा जो कमजोर नियोजन को इंगित करता है।

1.7 जिला नियोजन समितियां

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 63 और 86 के अन्तर्गत जिला पंचायतों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समग्र रूप से जिले के लिए उसमें क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों की विकास योजनायें सम्मिलित करते हुए एक विकास कार्यक्रम तैयार करना था और इसे जिला योजना समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना था जो उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के उपबन्धों के अन्तर्गत गठित की जानी थी। ऐसी समितियां अप्रैल 2008 में गठित की गयी जो दिसम्बर 2009 से क्रियाशील हुयी। इसके बावजूद 2009—10 में नमूना जांच की गयी 55 जिला पंचायतों की जिला विकास योजनाओं में क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों की विकास योजनायें सम्मिलित नहीं की गयी थी।

1.8 बजट तैयार किया जाना और बजट की प्रक्रिया

बजट तैयार किया जाना और बजट की तैयारी की प्रक्रिया वार्षिक बजट प्राक्कलनों की जांच और तदुपरान्त व्यय पर नियन्त्रण यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसे प्राधिकृत अनुदानों का विनियोजनों के अन्तर्गत सीमित रखा गया था, को निहित करती है। इस उद्देश्य के साथ प्रत्येक पंचायती राज संस्था को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत नियम

³ 307 क्षेत्र पंचायतों में से 7 क्षेत्र पंचायतों की वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की गयी थी इसलिए तालिका में सम्मिलित नहीं की गयी।

⁴ 3125 ग्राम पंचायतों में से 122 इकाइयों की वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की गयी थी, इसलिए तालिका में सम्मिलित नहीं की गयी।

संग्रह⁵ के उपबन्धों के अनुसार वार्षिक बजट तैयार करना था। वर्ष 2009-10 में 3,125 ग्राम पंचायतों और 307 क्षेत्र पंचायतों की नमूना जांच में पाया गया कि उनके द्वारा बजट तैयार नहीं किया गया था।

1.9 लेखांकन व्यवस्थाएँ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायतों के लिए बजट एवं लेखांकन प्रपत्रों का निर्धारण (2002) किया था। यद्यपि शासन ने (मार्च 2003) में संस्तुतियों को स्वीकार किया परन्तु जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लेखाओं का रख रखाव नहीं किया गया। यद्यपि ग्राम पंचायतों द्वारा लेखों को निर्धारित प्रपत्रों पर सनदी लेखाकारों से बनवाया जा रहा था लेकिन उनके लेखें सनदी लेखाकारों को सम्बद्ध करने में विलम्ब तथा सम्बद्धित सनदी लेखाकारों के समक्ष अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण तीन से छः वर्ष तक अवशेष थे।

बारहवें वित्त आयोग ने पाया कि पंचायतों को प्रदान की गयी वित्तीय स्वीकृति की सही जानकारी शासन स्तर पर उपलब्ध नहीं थी। तदनुसार यह संस्तुति की गयी कि शासन स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की निधियों का विश्वसनीय रख रखाव किया जाये जिससे पंचायती राज संस्थाओं की प्रत्येक स्तर पर वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किया जा सके। तथापि जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर लेखाओं की अनुपलब्धता के कारण इन लेखाओं का संकलन जनपद एवं शासन स्तर पर नहीं किया जा सका। जिसके परिणामस्वरूप निधि का आवंटन आवश्यकता आधारित निर्धारण पर आधारित नहीं था।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद एवं क्षेत्र समिति (बजट एवं सामान्य लेखा) नियम 1965 के अनुच्छेद 84 (2) में प्राविधानित है कि प्राप्ति एवं व्यय की प्रत्येक मद को कोषागार एवं बैंक विवरण के आधार पर प्रत्येक माह के अन्त में मिलान किया जायें तथा यदि कोई अन्तर हो तो उनका समाधान किया जाना चाहिए। तथापि नमूना जांच (2009-10) में पाया गया कि दस जिला पंचायतें एवं 17 क्षेत्र पंचायतों में धनराशि क्रमशः ₹9.72 करोड़ एवं ₹ 1.15 करोड़ (परिशिष्ट 1.2) 31 मार्च 2009 को असमाधानित थी। असमाधानित अन्तर के दुर्विनियोग/दुर्विनियोजन सम्भावित थे।

⁵ अनुच्छेद- 110 एवं 115

1.10 सम्प्रेक्षा प्रबन्ध

मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, पंचायती राज संस्थाओं की सभी त्रिस्तरीय लेखापरीक्षा हेतु प्राथमिक लेखापरीक्षक है।

फिर भी 2007-10 तक की अवधि में काफी मात्रा में पंचायतें अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण असम्प्रेक्षित थी, विवरण तालिका-8 में दिया गया है।

तालिका-8 इकाई की स्थिति प्रस्तावित, सम्प्रेक्षित एवं अवशेष

पंचायतों की संख्या	प्रस्तावित		सम्प्रेक्षित		अवशेष (प्रतिशत)	
	वर्तमान के विरुद्ध	अवशेष के विरुद्ध	वर्तमान के विरुद्ध	अवशेष के विरुद्ध	वर्तमान के विरुद्ध	अवशेष के विरुद्ध
2007-08						
जिला पंचायतें	70	161	23	30	47(67)	131(81)
क्षेत्र पंचायतें	809	4,680	22	27	787(97)	4,653(99)
ग्राम पंचायतें	51,772	1,84,795	14,623	11,006	37,149(72)	1,73,789(94)
2008-09						
जिला पंचायतें	70	175	24	48	46(66)	127(73)
क्षेत्र पंचायतें	809	5,430	36	90	773(96)	5,340(98)
ग्राम पंचायतें	51,772	2,13,227	18,868	18,490	32,904(64)	1,94,737(91)
2009-10						
जिला पंचायतें	70	169	29	58	41(59)	111(66)
क्षेत्र पंचायतें	810	6,091	73	291	737(91)	5,800(95)
ग्राम पंचायतें	51,977	2,24,725	23,988	28,670	27,989(54)	1,96,055(87)

(स्रोत: मुख्य लेखापरीक्षाधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें)

अधिकांश पंचायतों की सम्प्रेक्षा 2007-10 की समयावधि में न होने की वजह से उनका वित्तीय विवरण वास्तविकता पर आधारित एवं विश्वसनीय नहीं था।

1.11 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को तकनीकी मार्गदर्शक एवं पर्यवेक्षण के लिए सम्प्रेक्षा को सौंपे जाने की स्थिति

ग्यारहवें वित्त आयोग ने पंचायतों के लेखों का उचित लेखांकन एवं तकनीकी मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण एवं उनकी सम्प्रेक्षा के लिए नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की अनुसंशा अग्रसारित की थी। इस क्रम में सरकार द्वारा (अक्टूबर 2001) स्थानीय संस्थाओं की लेखा परीक्षा को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के धारा 20 (1) के अन्तर्गत सौंपा गया था। इसी क्रम में पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा सम्पादित की गयी तथा (2003-10) 15,876 सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन निर्गत कर 12,364 प्रस्तर मुख्य

सम्प्रेक्षा अधिकारी को निस्तारित के लिए प्रेषित किये गये। यद्यपि उक्त प्रस्तर दिसम्बर 2010 तक अनुत्तरित थे।

2009-10 की अवधि में 55 जिला पंचायतें, 307 क्षेत्र पंचायतें एवं 3,125 ग्राम पंचायतों की नमूना जांच में 2,786 प्रस्तर खराब वित्तीय प्रबन्धन एवं वित्तीय अनियमितता के परिणामस्वरूप निष्फल, व्ययाधिक्य, निधि का स्थानान्तरण एवं आय पर हानि आदि को कार्यालय प्रमुख, निदेशक पंचायती राज तथा मुख्य सम्प्रेक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें को अग्रेसित किया गया। यद्यपि इन प्रस्तरों का निस्तारण (दिसम्बर 2010) प्रतीक्षित था।

1.12 अन्य बिन्दु

द्वितीय राज्य वित्त आयोग ने 245 संस्तुतियों की थी जिसमें मुख्य रूप से अनुदान का समय पर निर्गत किया जाना, पंचायतों के निजी स्रोतों में वृद्धि करना, जिला पंचायत की आय को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण, पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों को गतिमान आदि था। सरकार ने 133 संस्तुतियों को मूलतः, 70 को आंशिक रूप से स्वीकार किया था, किन्तु 42 संस्तुतियां जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति पर करारोपण, भूमि उपार्जन की दरों में परिवर्तन एवं पंचायतों की आय में वृद्धि हेतु लाइसेंस शुल्क आदि से सम्बन्धित थी, को स्वीकार नहीं किया।

1.13 निष्कर्ष

इस प्रकार बजटिंग एवं बजट प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करने एवं लेखा अभिलेखों को निर्धारित प्रपत्रों में नहीं बनाये जाने के परिणामस्वरूप पंचायतों की आय एवं व्यय का सत्य एवं निष्पक्ष-दृश्य उपलब्ध नहीं था। बकाया सम्प्रेक्षा के कारण उपलब्ध वित्तीय आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे। निधि उपलब्धता के बावजूद भी तीन स्तरों यथा जनपद, राज्य तथा केन्द्र में से किसी एक स्तर पर डाटा बेस विकसित नहीं किया गया था। जिला नियोजन समिति अधिनियम 1999 के प्रभावी होने के ग्यारह वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी जिला नियोजन समितियां प्रयोजन मूलक नहीं थी परिणाम स्वरूप उनके द्वारा जनपद स्तर पर विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों का नियोजन एवं अनुश्रवण नहीं किया जा सका।

अध्याय-II

निष्पादन लेखापरीक्षा

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की प्राप्ति एवं उपभोग की निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सार

भारत सरकार ने (जनवरी 2007) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) योजना को प्रारम्भ किया था जिसका उद्देश्य विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना तथा स्थानीय संसाधनों एवं अन्य विकास के लिए आवश्यकताओं के बीच अन्तर को कम करना था जो मौजूदा व्यवस्था के अन्तर्गत ठीक नहीं हो पा रही थी को अच्छादित किया जाना था। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का अपेक्षित परिणाम पिछड़े जनपदों में गरीबी उन्मूलन एवं उत्तरदायी पंचायतों को विकसित करना था। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का मतंव्य वित्तीय संसाधनों को हस्तान्तरित कर देश के 250 जिलों में हो रहे विकास कार्यों को जारी रखना है। उत्तर प्रदेश के 34 जिले इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए चुने गये हैं।

प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की प्राप्ति एवं उपभोग की निष्पादन लेखा परीक्षा (2006-10) में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये-

- बी आर जी एफ कार्यक्रम संदर्शी योजना बनाकर लागू किया जाना था। मार्च 2010 में 34 बीआरजीएफ जिलों में से मात्र 25 जिलों में संदर्शी योजना तैयार की गयी थी वर्ष 2007-09 हेतु ₹ 1,306.99 करोड़ की वार्षिक योजना उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा पारित किये बिना ही संदर्शी योजना तैयार की गयी थी।
- संदर्शी योजना के अनुरूप वार्षिक योजना तैयार कर जिला नियोजन समिति को अग्रेसित करना था एवं उच्च शक्ति प्राप्त समिति को योजना कार्यान्वयन हेतु पारित करना था। मई 2008 तक जिला योजना समिति गठित नहीं की गई थी एवं वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु ₹ 510.20 करोड़ भारत सरकार द्वारा निर्गत नहीं किया गया था।
- दिशा निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए उनकी जनपदीय जनसंख्या के अनुपात में उपयोजना तैयार किया जाना था। वर्ष 2009-10 तक उपयोजना तैयार नहीं की गयी थी।
- राज्य सरकार भारत सरकार से वर्ष 2006-10 के दौरान ₹ 1,268.24 करोड़ (कुल प्राप्त होने वाले अनुदान का 52 प्रतिशत) का अनुदानप्राप्त करने में अक्षम थी क्योंकि

आवश्यक नियोजन जैसे जिला नियोजन समिति का गठन, संदर्शी योजना की तैयारी इत्यादि का अभाव था।

- अनुदान के अन्तः वितरंग के अंकित सूत्रों को न अपनाने के कारण वर्ष 2009-10 में जिला पंचायत को अंश के रूप में राज्य सरकार से ₹103.75 करोड़ अधिक प्राप्त हुआ था जिसमें स्थानीय शहरी निकायों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों का अंशभी था।
- दिशा निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त करने के 15 दिनों के अन्दर राज्य सरकार द्वारा सीधे पंचायतों के बैंक खातों में हस्तान्तरित किया जाना था। उसके सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा जिला नोडल एजेंसी के माध्यम से हस्तान्तरण के कारण 15 दिनों से 12 माह तक के विलम्ब से हस्तान्तरण के कारण ₹ 5.84 करोड़ ब्याज दायित्व के रूप में था। जिला पंचायत राज अधिकारियों के पास ₹ 1.36 करोड़ (जुलाई 2010 तक) बिना आहरण के पड़ा हुआ था।
- योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार पंचायतों को क्षमता संवर्धन हेतु ₹ एक करोड़ प्रतिवर्ष प्रति जिला, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि प्राप्त होनी थी। जिससे योजना की सहभागिता, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जाना था। राज्य सरकार इस तरह के नियोजन तैयार करने में असमर्थ थी। इस प्रकार राज्य सरकार भारत सरकार से ₹ 90.44 करोड़ की धनराशि प्राप्त करने में असफल रही।
- राज्य सरकार ने ग्राम सचिवालय निर्माण हेतु कार्यदायी संस्थाओं को सेवा कर के रूप में ₹ 12.68 करोड़ भुगतान किया था जिसकी आवश्यकता नहीं थी।

2.1 परिचयात्मक

भारत सरकार नेबीआर जी एफ योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) हेतु प्रारम्भ की थी (जनवरी 2007)। इस योजना का उद्देश्य राज्य के 34 पिछड़े जिलों⁶ में क्षेत्रीय विषमता को दूर करना, स्थानीय प्रशासन को दायित्व देकर, पिछड़े जिलों में कमजोर वर्गों की गरीबी को मिटाना एवं विकास के लिए दी जाने वाली राशि के प्रवाह में वृद्धि करने तथा उसे समन्वित करने के लिए सहायता प्रदान करना था। राज्य में पहले 21 जिलों में राष्ट्रीय सम विकास योजना को क्रियान्वित करते हुये बाद में 13 जिलों⁷ को वर्ष 2006-07 में बीआर जी

⁶ परिशिष्ट-1.1 में प्रदर्शित।

⁷ अम्बेडकर नगर, श्रवास्ती, फर्रुखाबाद, संतकबीर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, बस्ती, बहराइच, एटा, गोण्डा, बदायूं एवं लखीमपुर खीरी।

एफ योजना में समाहित किया गया। बी आर जी एफ योजना के वित्त पोषण के दो लक्ष्य थे:—

- i. पंचायत स्तर की शासन व्यवस्था को समता सृजन के माध्यम से पर्याप्त सुदृढ़ करना ताकि स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहभागिता पूर्ण नियोजन, निर्णय करने, क्रियान्वयन और निगरानी में मदद मिले एवं
- ii. पिछड़े क्षेत्रों को अन्य विकास की आवश्यकताओं तथा स्थानीय संसाधनों के अन्तर को कम करने के लिए विकासशील असम्बद्ध अनुदान उपलब्ध कराना। प्रत्येक जिला नियोजन में पिछड़ेपन के आधार पर सर्वे करते हुये संदर्शी योजना जनसहभागिता के अनुसार तैयार की जानी थी। उक्त कार्यो हेतु पेशेवर एवं आउटसोरसिंग वाह्य कुशल लोगों से सहायता अनुमन्य थी। जिला संदर्शी योजना सहभागिता के आधार पर तृणमूल से जिला स्तर तक तैयार किया जाना था जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिहेतु उपयोजना का निर्धारण सुनिश्चित किया जाना था।

2.2 संगठनात्मक ढांचा

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के लिए राज्य स्तर पर पंचायती राज विभाग नोडल विभाग था। पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव, एवं योजना निदेशक क्रमशः उच्च शक्ति प्राप्त समिति एवं योजना प्रबन्ध इकाई के प्रमुख मनोनीत किये गये थे। इनका कार्य जिला योजना समितियों द्वारा तैयार कार्य योजनाओं को मन्जूरी, प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना था। जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबन्ध इकाई का गठन (अगस्त 2009 में) किया गया जिसमें अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सदस्य सचिव मनोनीत किये गये हैं। जो योजना कोप्रस्तुत, प्रबन्ध एवं निगरानी का कार्य करेंगे। जिला स्तर पर जिला पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत योजना की कार्यदायी संस्थाएं थी।

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निम्नलिखित को सुनिश्चित करने हेतु समीक्षा की गयी कि क्या :—

- पिछड़ा क्षेत्रों की चयन व्यवस्था एवं प्रोजेक्ट के नियोजन विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है जैसा कि भारत सरकार द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना की मार्ग दार्शिका में वर्णित था।

- भारत सरकार द्वारा निधियों का निर्धारण एवं प्रेषण जारी दिशा निर्देशों के अनुसार था तथा पंचायती राज संस्थाओं की निधियों का हस्तान्तरण एवं उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार किया गया था।
- परियोजनाओं का क्रियान्वयन उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त था एवं दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित चयनित/नामित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया गया था।
- विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण व्यवस्था लागू थी तथा प्रभावी ढंग से क्रियाशील थी।

2.4 लेखापरीक्षा का अभिप्राय एवं कार्य प्रणाली

इस योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा की आच्छादित अवधि वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक थी। राज्य स्तर पर पंचायती राज विभाग एवं योजना प्रबन्ध इकाईकुल चयनित 34 बी आर जी एफ जिलों में से पी पी एस डब्लू ओ आर नमूना पद्धति से 9 जिला पंचायतें⁸ एवं प्रत्येक चयनित जनपद कीएस आर एस डब्लू ओ आर नमूना पद्धति से चयनित दो क्षेत्र पंचायतों⁹ के अभिलेखों की जाँच की गयी थी जाँच के लिए कार्यों के चयन का आधार सर्वाधिक व्यय था।

राज्य सरकार ने परिचात्मक गोष्ठी (जून 2010) में जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की चयन पद्धति एवं लेखा परीक्षा कार्य क्षेत्र तथा कार्य प्रणाली पर सहमति प्रदान की थी। लेखा परीक्षा आपत्तियों सरकार को नवम्बर (2010) में प्राप्त करा दी गयी थी। समापन गोष्ठी दिसम्बर 2010 में सम्पन्न हुयी थी जिसमें तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की गयी तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गयी थी।

लेखा परीक्षा आपत्तियां

2.5 नियोजन

2.5.1 संदर्शी योजना तैयार किये जाने में विलम्ब

योजना की मार्ग दर्शिका के अनुसार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम का शुभारम्भ प्रत्येक चयनित जनपद में उसके पिछड़ेपन के गहन अध्ययन के साथ करना था इस अध्ययन में बेस लाइन सर्वे भी सम्मिलित था। इसके बाद इस पिछड़ेपन के समाधान के लिए 2006–07 और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बड़ी सूज बूझ से सहभागिता पूर्ण जिला

⁸ लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, कुशीनगर, जौनपुर, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, श्रावस्ती एवं प्रतापगढ़।

⁹ रनिया बेहड़, फूल बेहड़, बदलगाँज, बेलाघाट, निगुंहा— नौरंगिया, रामकोला, मछलीशहर, रामपुर, राबर्टसगंज, चोपन, हरपालपुर, संडीला, परसन्डी, खैराबाद, सिरिसया, जमुनाहा, कुन्डा, एवं प्रतापगढ़ सदर।

विकास संदर्शी योजना तैयार करना था। उक्त योजना तकनीकी सहायता संस्थान की मदद लेकर तैयार करना था। परियोजना प्रबन्धन इकाई के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि भारत सरकार ने पांच विभिन्न संस्थाओं को अक्टूबर 2007 में इन योजनाओं को तैयार करने के लिये निर्देशित किया था। सरकार ने एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ (ए फ सी) को जून 2009 में 14 जिलों¹⁰ के लिये कार्यादेश दिया था एवं पुनः सितम्बर 2009 में 11 जिलों¹¹ के लिये कार्यादेश दिया गया था जिसके तहत कार्य 2009 तक पूर्ण किया जाना था। वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 की वार्षिक योजना क्रमशः मार्च 2008 तक तथा अक्टूबर 2009 तक तैयार किये जाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। इसके साथ भारत सरकार द्वारा उनके बचनबद्ध होने से 19 से 22 माह बाद संदर्शी योजना बनाया जाना था। यद्यपि 25 जनपदों की संदर्शी योजना एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने मार्च 2010 तक तैयार की थी। जून 2010 तक शेष नौ जिलों की संदर्शी योजना तैयार करने हेतु किसी तकनीकी सहायता संस्थान से अनुबन्ध नहीं किया गया।

परिणामतः 34 जनपदों की ₹1306.99 करोड़ की वार्षिक जिला योजना बिना संदर्शी योजना तैयार किये हुये उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अनुमोदित कर दी थी, जिसका विवरण निम्नवत था।

तालिका-1: वार्षिक जिला योजना

वर्ष	उच्चाधिकार समिति द्वारा अनुमोदित माह	वार्षिक योजना की कुल धनराशियां (₹ करोड़ में)
2007-08	जुलाई सितम्बर 2008	629.56
2008-09	अगस्त-सितम्बर 2009	677.43

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर परियोजना प्रबन्धन इकाई ने उत्तर में बताया (जुलाई 2010) कि ए एफ सी के अतिरिक्त किसी भी एजेन्सी ने कार्य पूर्ण करने में रुचि नहीं दर्शायी जिसके परिणामस्वरूप ए एफ सी को 25 जनपदों का कार्य सौंपा गया। इस प्रकार किसी तकनीकी सहायता संस्थान द्वारा योजना तैयार करवाने में सहमत न होना एवं उस पर सरकार द्वारा निर्णय करने में विलम्ब किये जाने के कारण ए एफ सी को कार्य सौंपने में विलम्ब हुआ। यद्यपि ए एफ सी के प्रतिवेदन में उद्धृत अधिकतर परियोजनाएं जिसमें विषमताएं थी, जैसे दुग्ध संग्रह केन्द्र, जल का संचयन, आपदा प्रबन्धन इत्यादि को उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित नियोजन में सम्मिलित नहीं किया गया था।

¹⁰ बाराबंकी, बस्ती, बदायूँ, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, संतकबीरनगर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोण्डा, जौनपुर, जालौन एवं लखीमपुर खीरी।

¹¹ बहराइच, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, सीतापुर, अम्बेडकरनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, आजमगढ़, ललितपुर एवं चन्दौली।

2.5.2 संदर्शी योजना बनाने में जनसहभागिता (की उपेक्षा किया जाना या) को सुनिश्चित न किया जाना

योजना के दिशा निर्देशों में यह प्रावधान किया गया था कि संदर्शी योजना तैयार करने में जनसहभागिता सुनिश्चित की जायेगी उक्त हेतु सरकार एवं एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड के मध्य एम ओ यू की शर्तों में इसका उल्लेख किया गया था। संदर्शी योजना की संवीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने जनसहभागिता का निर्धारण कैसे किया था?

छ: जिला पंचायतों¹² के नमूना जांच (जून-जुलाई 2010) में इस ओर इंगित किये जाने पर अपर मुख्य अधिकारियों ने बताया कि उन्हें न तो उक्त तथ्यों के सर्वे का ज्ञान था और न ही उनसे इस पर विचार विमर्श ही किया गया था। यद्यपि सरकार ने आश्वस्त (दिसम्बर 2010) किया कि एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड को जनसहभागिता के अभिलेख तैयार करने का निर्देश दिया जायेगा।

2.5.3 वर्तमान व्यवस्था में उपलब्ध संरचनात्मक एवं विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के अन्तर की प्राथमिकता का निर्धारण न करना।

योजना के दिशा निर्देशों में प्राविधानित था कि जिले की संदर्शी योजना तैयार की जायेगी एवं प्रत्येक जनपद की प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करते हुये उन्हीं के अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना था। नौ जनपदों के नमूना जांच में पाया गया कि उनमें से छः¹³ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में मौजूदा व्यवस्था के अन्तर्गत संरचनात्मक एवं विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के अन्तर की प्राथमिकता का निर्धारण एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड के मध्य ए एम यू की शर्तों में सम्मिलित नहीं किया गया था। अतः विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की प्राथमिकताओं से सम्बन्धित दिशा निर्देश, जो जनपद में विशेष रूप से आवश्यक थे, का अनुपालन नहीं किया गया था।

2.5.4 जिला योजना समिति का विलम्ब से गठन करना।

योजना के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड डी के अन्तर्गत गठित जिला योजना समिति से पारित वार्षिक जिला योजना को धन प्राप्त करने के लिये पंचायती राज मंत्रालय को अपनी मांग प्रेषित करने से पूर्व उच्च शक्ति प्राप्त समिति से अनुमोदन लेना था। मई 2008 तक जिला योजना समितियां गठित नहीं थी एवं भारत

¹² लखीमपुर खीरी, जौनपुर, सोनभद्र, सीतापुर, श्रावस्ती एवं प्रतापगढ़।

¹³ लखीमपुर खीरी, जौनपुर, सोनभद्र, सीतापुर, श्रावस्ती एवं प्रतापगढ़।

सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए निर्धारित ₹ 510.28 करोड़ अवमुक्त नहीं किया गया था। 2007-08 की कार्ययोजना की प्रथम किस्त ₹ 541.74 करोड़ वित्तीय वर्ष 2008-09 में निर्गत किया गया था। अतएव जिला योजना समिति का विलम्ब से गठन होने के कारण वित्तीय वर्ष 2006-07 की धनराशि व्ययगत हो गयी एवं 2007-08 की धनराशि भारत सरकार से विलम्ब से प्राप्त हुयी थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर परियोजना निदेशक योजना प्रबन्धन इकाई ने स्वीकार किया (जुलाई 2010) था कि जिला योजना समिति के गठन में विलम्ब के कारण वित्तीय वर्ष 2006-07 की कार्ययोजना तैयार नहीं की गयी थी एवं 2007-08 की कार्य योजना विलम्ब से तैयार की गयी थी। अतएव नियोजन की कमी के कारण सरकार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को प्राप्त करने तथा उसका उपभोग करने में असमर्थ थी।

2.5.5 अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए उपयोजना तैयार न किया जाना

योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में उपयोजना तैयार करना था। नमूना जांच की गई जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के अभिलेखीय संवीक्षा में पाया गया कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये उपयोजना तैयार नहीं की गयी थी। वर्ष 2007-08 की वार्षिक योजना बिना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की उपयोजना के पारित की गयी थी, जबकि पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधि भी तृतीय एवं चतुर्थ बैठक जो क्रम'तः 15.09.2008 एवं 09.01.2009 को आयोजित की गयी, में उपस्थित थे। अतः अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य बी.आर.जी.एफ. अनुदान के लाभ से वंचित थे। लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत ने उत्तर में कहा कि (जून-जुलाई 2010) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अलग से उपयोजना तैयार नहीं की गयी थी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2009-10 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उपयोजना तैयार किये जाने के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था।

2.6 वित्तीय प्रबन्धन

राज्य को बी.आर.जी.एफ. से वर्षवार प्राप्त अनुदान एवं उपभोग¹⁴ का विवरण निम्नवत था:—

तालिका-2: बी.आर.जी.एफ. की वित्तीय स्थिति (2006-10)

(₹ करोड़ में)

क्र. म.	वर्ष	अनुदान का उद्देश्य	आवंटन	अवमुक्त	उपयोग	धनराशि प्रदान नहीं की गयी/कम प्रदान की गयी
1	2006-07	क्षमता संवर्धन	34.00	0.00	0.00	34.00
		विकासात्मक अनुदान	476.28	0.00	0.00	476.28
2	2007-08	क्षमता संवर्धन	34.00	25.30	21.20	8.70
		विकासात्मक अनुदान	602.09	3.40	0.50	598.69
3	2008-09	क्षमता संवर्धन	34.00	0.00	0.00	34.00
		विकासात्मक अनुदान	602.09	541.74	433.32	60.35
4	2009-10	क्षमता संवर्धन	34.00	20.26	0.00	13.74
		विकासात्मक अनुदान	602.09	559.61	625.66 ¹⁵	42.48
		कुल	2,418.55	1,150.31	1,080.68	1,268.24

2.6.1 वित्तीय स्थिति

34 बी.आर.जी.एफ. जनपद पंचायती राज मंत्रालय के अनुमोदित एवं वार्षिक योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006-07 में ₹ 476.26 करोड़ तथा 2007-08 में ₹ 602.09 करोड़ प्रतिवर्ष प्राप्त करने के हकदार थे, अग्रेत्तर वर्ष 2007-08 की प्रथम किस्त के तहत पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ₹ 541.74 करोड़ की धनराशि वर्ष 2008-09 में अवमुक्त की गयी थी, वर्ष 2007-08 की द्वितीय किस्त की धनराशि वर्ष 2006-07 एवं 2008-09 की पात्रता के विरुद्ध अनुदान अवमुक्त नहीं किया गया क्योंकि आवश्यक नियोजन एवं संसाधन बनाने की प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला नियोजन समिति का गठन सीधे धनराशि को पंचायतों के खातों में हस्तान्तरण की व्यवस्था का क्रियान्वयन तथा सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इस प्रकार सरकार वर्ष 2006-10 के

¹⁴ 34 बी0आर0जी0एफ0 जनपद का आवंटन एवं अवमुक्त धनराशि में पंचायती राज संस्थाएं एवं स्थानीय निकायों दोनों सम्मिलित।

¹⁵ ₹ 108.42 करोड़ वर्ष 2008-09 की अवशेष धनराशि का उपयोग इस वर्ष में सम्मिलित है।

दौरान ₹ 2,418.55 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹ 1,268.24 करोड़ (आवंटन का 52.44 प्रतिशत) प्राप्त करने में असफल रही एवं कुल प्राप्त धनराशि ₹1,150.31 करोड़ में से केवल ₹ 1,080.68 करोड़ (प्राप्त धनराशि का 94 प्रतिशत) का उपयोग किया गया था, जिसके कारण योजना का उद्देश्य विकास में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने एवं विकास योजनाओं में सेतु का काम करने हेतु लागू की गयी योजना का आंशिक लाभ ही मिल सका, उद्धृत किये जाने पर परियोजना, निदेशक पी.एम.यू. ने स्वीकार (जुलाई 2010) किया कि जिला योजना समिति का विलम्ब से जिला स्तर पर गठन होने के कारण ढांचागत सुधारों को लागू करने के लिए योजना को तैयार करने में विलम्ब के कारण निधि के प्राप्त होने में विलम्ब हुआ।

2.6.2 निधि प्रवाह प्रक्रिया का अनुपालन न किया जाना

बी.आर.जी.एफ. में धनावंटन की दो प्रक्रियाएं हैं (i) क्षमता संवर्धन निधि एवं (ii) संयुक्त विकास निधि। प्रत्येक बी.आर.जी.एफ. जनपद क्षमता संवर्धन हेतु एक करोड़ रुपया प्रतिवर्ष प्राप्त करेगा। संयुक्त विकास निधि को जनपदों के मध्य कम से कम निर्धारित ₹10 करोड़ के हिसाब से प्रतिवर्ष प्रति जनपद वितरित किया जायेगा एवं शेष आवंटन प्रत्येक जनपद में जनसंख्या के अनुपात, बी आर जी एफ जनपदों के क्षेत्रफल तथा जनपदों के क्षेत्रफल एवं कुल जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाना था। सरकार सामान्य समीकरण के आधार पर बी आर जी एफ अनुदान जनपद के पंचायतों के मध्य आवंटन करती थी। निधि को वितरित करने के लिए स्थानीय निकाय एवं पंचायतों के बीच क्रमशः 20:80 का अनुपातनिर्धारित किया गया था। जबकि त्रिस्तरीय पंचायतों में निधि का वितरण 70:10:20 के आधार पर क्रमशः ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों में किया जाना था।

भारत सरकार ने वर्ष 2009-10 में अवमुक्त ₹ 559.61 करोड़ की धनराशि में से पंचायतों को ₹ 494.39 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जो देय राशि ₹ 447.67 करोड़ के विरुद्ध थी तथा ₹ 46.42 करोड़ स्थानीय निकाय के हिस्से को जिला पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया। इसके अलावा क्षेत्र पंचायतों का ₹ 28.07 करोड़ एवं ग्राम पंचायतों का ₹ 28.96 करोड़ हिस्सा भी जिला पंचायतों को हस्तान्तरित किया गया। परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को कम निधि अवमुक्त की गयी। जैसा **परिशिष्ट-2.1** उद्धृत है। परिशिष्ट दर्शाता है कि पांच जिला पंचायतों को ₹4.69 करोड़ कम अवमुक्त किया गया तथा शेष 29 जिला पंचायतों को ₹ 108.44 करोड़ देय अंशराशि से अधिक अवमुक्त की गयी।

इस प्रकार स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के मध्य पंचायती राज संस्थाओं के बीच सामान्य सारिणी का अनुपालन नहीं किया गया था। जिसके कारण जनपद के विभिन्न पंचायतों में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने हेतु कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

2.6.3 जिला पंचायत राज अधिकारियों के पास अवितरित धनराशि

योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार निधि को पंचायतों के खातों में हस्तान्तरण सीधे बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत किया जाना था। सरकार निधि को पंचायतों के खातों में सीधे हस्तान्तरण न करके वर्ष 2007-08 में नामित जिला पंचायत राज अधिकारियों को जो जिला नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे थे एवं वर्ष 2008-09 तथा आगामी वर्षों हेतु सम्बन्धित जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारियों (मई 2009) को सम्बन्धित पंचायतों को हस्तान्तरण हेतु नामित किया गया था। इस प्रकार जिला नोडल एजेंसी द्वारा निधि का पंचायतों को हस्तान्तरण अनियमित था जिसके कारण निधियों का विलम्ब से हस्तान्तरण किया गया।

नौ जनपदों की नमूना जांच में पाया गया कि छः जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा ₹ 1.36 करोड़ जुलाई 2010 तक अवितरित रखा गया जिसका विवरण निम्नवत है।

तालिका-3: जिला पंचायत राज अधिकारियों के पास अवितरित धनराशि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	जि.प.रा.अ. के पास अवितरित धनराशि	प्राप्त ब्याज की धनराशि	योग
		बी.आर.जी.एफ. अनुदान की अवितरित धनराशि		
1	हरदोई	00.00	12.17	12.17
2	लखीमपुर खीरी	00.00	10.95	10.95
3	सोनभद्र	00.00	18.19	18.19
4	गोरखपुर	00.00	11.57	11.57
5	कुशीनगर	00.00	33.92	33.92
6	प्रतापगढ़	42.75	6.62	49.37
	योग	42.75	93.42	136.17

इंगित किये जाने पर सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारियों ने अवगत (जुलाई 2010) कराया कि सरकार से निधि के हस्तान्तरण हेतु कोई निर्देश न मिलने के कारण सम्बन्धित राशि उनके पास पड़ी हुई थी। सरकार की अक्षमता के कारण निधि के हस्तान्तरण हेतु

जिला पंचायत राज अधिकारियों को निर्देश न निर्गत करने के कारण ₹ 1.36 करोड़ तेरह माह से अधिक समय से अप्रयुक्त थी।

2.6.4 बी.आर.जी.एफ. अनुदान पर अप्राप्त ब्याज

जिला पंचायत राज अधिकारी सीतापुर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि बी.आर.जी.एफ. अनुदान की धनराशि ₹ 16.68 करोड़ लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सीतापुर में बचत खाते में 02.01.2009 से 28.02.2009 तक जमा थी लेकिन इस अवधि में 3.5 प्रतिशत की दर से अर्जित ब्याज ₹ 9.73 लाख को खाते में जमा नहीं दर्शाया गया था। इस सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी ने (जुलाई 2010) अवगत कराया कि प्रकरण बैंक के समक्ष उद्धृत किया गया है।

2.6.5 बी.आर.जी.एफ. योजना की अनुदान के लिए अलग से रोकड़ बही का रख रखाव न किया जाना।

बी.आर.जी.एफ. योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार योजना हेतु अलग से रोकड़ बही का रख रखाव के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना था। जांच की गई 9 जिला पंचायतों तथा जिला पंचायत कुशीनगर में इन प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। यद्यपि कि इकाई ने अपने उत्तर में यह आश्वासन (जुलाई 2010) दिया था कि आगामी वित्तीय वर्ष से अलग से रोकड़ बही बनाई जायेगी।

2.7 क्रियान्वयन

2.7.1 पंचायती राज संस्थाओं को निधि हस्तान्तरण में विलम्ब के कारण ब्याज की धनराशि ₹ 5.84 करोड़ के दायित्वों का सृजन

योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि को 15 दिन के उपरान्त पंचायतों के खातों में हस्तान्तरित करने पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दर पर दण्डात्मक ब्याज का प्राविधान किया गया था।

नौ जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि सरकार द्वारा धनराशि को सम्बन्धित पंचायतों को हस्तान्तरण करने में 15 दिन से 12 महीने तक का विलम्ब किया गया था। पंचायतों को पी.एम.यू. एवं डी.एन.ए. स्तर से विलम्ब से धनराशि का हस्तान्तरण करने के कारण से ₹ 5.84 करोड़ (नौ जिलों की नमूना जांच) दण्डात्मक ब्याज 11.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भुगतान करना सरकार का दायित्व था, (परिशिष्ट 2.2)

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर पी.एम.यू. (जुलाई 2010) ने अवगत कराया कि जिला नोडल संस्थाओं (सम्बन्धित जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारी) से बैंक खाता संख्या प्राप्त कर ली गयी है तथा वर्ष 2010-11 से बैंकों में निधि के हस्तान्तरण की कार्यवाही की जायेगी, इस प्रकार योजना के क्रियान्वयन के चार वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी सरकार इस स्थिति में नहीं थी कि निधि की धनराशि को सीधे सम्बन्धित पंचायतों के बैंक खाते में हस्तान्तरित कर सके।

2.7.2 बी.आर.जी.एफ. अनुदान की धनराशि पर ₹ 32.24 लाख ब्याज की हानि

जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती तथा जौनपुर को ₹ 10.84 करोड़ तथा ₹ 16.28 करोड़ क्रमशः दिनांक 11.12.2008 तथा 30.01.2009 को प्राप्त हुआ। जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती ने निधि को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के वैयक्तिक लेजर खाता में जमा किया था जबकि जिला पंचायत राज अधिकारी, जौनपुर ने यूनियन बैंक आफ इण्डिया जौनपुर के विविध बैंक खाते में जमा किया। जिला पंचायत राज अधिकारी श्रावस्ती ने 30.05.2009 से 26.09.2009 के दौरान सम्बन्धित पंचायतों को भुगतान किया, जबकि जिला पंचायत राज अधिकारी जौनपुर ने ₹ 2.93 करोड़ का भुगतान दिनांक 24.03.2009 को तथा शेष धनराशि ₹ 13.35 करोड़ दिनांक 30.05.2009 से 03.06.2009 के दौरान किया गया जिसके कारण ब्याज के रूप में ₹ 32.24 लाख की क्षति हुई (@3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से)।

इस सम्बन्ध में इंगित करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी, श्रावस्ती (अगस्त 2010) ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी के आदेश से धनराशि को पी एल ए में जमा किया गया, यद्यपि जिला पंचायत राज अधिकारी जौनपुर (अगस्त 2010) ने अवगत कराया कि निधि को लम्बित अन्तिम वितरण तक विविध बैंक खाते में जमा किया गया था। इस प्रकार योजना के दिशा निर्देशों का परिपालन न करने के कारण बी आर जी एफ अनुदान पर ₹ 32.24 लाख ब्याज की हानि हुई।

2.7.3 क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का क्रियान्वयन न किया जाना

सरकार को क्षमता संवर्धन में वृद्धि एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु समस्त सहभागियों को प्रशिक्षण देकर इस योग्य बनाना था कि वे योजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण कर सकें। इस हेतु ₹ 136.00 करोड़ को 34 बी आर जी एफ जनपद के लिए अवमुक्त करने का प्रावधान था। इस उद्देश्य हेतु समयावधि 2006-10 तक पंचायती राज मंत्रालय को ₹ एक करोड़ प्रति जनपद प्रति वर्ष की दर से अवमुक्त करना था। पी एम यू

द्वारा तैयार की गयी वार्षिक योजना क्षमता संवर्धन हेतु राष्ट्रीय क्षमता संवर्धन फ्रेमवर्क के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार नहीं की गयी थी जिसकी वजह से सरकार को केवल ₹ 45.56 करोड़ की धनराशि ही जुलाई 2010 तक प्राप्त हो सकी। उक्त निधि में से सरकार ने केवल ₹ 25.30 करोड़ (जुलाई 2010) सम्बन्धित जिलों को हस्तान्तरित की थी। यद्यपि परियोजना प्रबन्धन इकाई (पी.एम.यू.) ने ₹ 86.96 करोड़ की योजना दिसम्बर 2009 में पंचायती राज मन्त्रालय (एम.ओ.पी.आर.) को प्रेषित की थी, लेकिन अवशेष धनराशि भारत सरकार ने जुलाई 2010 तक शासन को अवमुक्त नहीं की थी। इस प्रकार सरकार क्षमता संवर्धन के लिए सम्पूर्ण प्राधिकृत धनराशि प्राप्त करने में विफल रही तथा आंशिक प्राप्त धनराशि का ही उपयोग कर सकी।

उत्तर में परियोजना प्रबन्धन इकाई ने अवगत (जुलाई 2010) कराया कि अवशेष धनराशि को अवमुक्त करने के लिए पत्र व्यवहार किया जा रहा था।

2.7.4 अनाधिकृत धनराशि ₹12.68 करोड़ का हस्तान्तरण एवं ₹ 38.54 करोड़ का परिहार्य व्यय

दिशा निर्देशों में डी.पी.सी. द्वारा कार्यदायी संस्थाओं के चयन का प्राविधान था। सरकार द्वारा जिला योजना समिति के बावजूद सरकार ने स्वयं कार्यकारी संस्थाओं (यू.पी.पी.सी.एल., यू.पी.एस.के.एन.एन.एल. एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा (आर.ई.एस.) को निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु नामित किया था।

परियोजना प्रबन्धन इकाई के अभिलेखों की जांच (जून-जुलाई 2010) एवं जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं कार्यकारी संस्थाओं की नमूना जांच में पाया गया कि सड़क, सेतु, नाली, चेक डैम, रपटा, ग्राम पंचायत सचिवालय आदि का निर्माण जिला पंचायत द्वारा किया जा रहा था। सड़कें, सेतु, नाली संसाधन केन्द्रों आदि का निर्माण क्षेत्र पंचायत द्वारा एवं ग्राम पंचायत सचिवालय सड़कें, आंगनबाड़ी केन्द्रों आदि का निर्माण कार्यदायी संस्थाएँ (यू.पी.पी.सी.एल., यू.पी.एस.के.एन.एन.एल. एवं आर.ई.एस.) द्वारा किया जा रहा था।

सरकार ने ग्राम पंचायत सचिवालयों के निर्माण के लिए न्यूनतम लागत को ध्यान में नहीं रखा एवं प्रतिस्पर्धात्मक न्यूनतम दरों को ध्यान में रखे बिना ही सरकार ने यू.पी.पी.सी.एल. एवं यू.पी.एस.के.एन.एन.एल. को ₹ 14.72 लाख प्रति सचिवालय के दर से निर्माण का कार्य सौपा गया। यू.पी.पी.सी.एल. एवं यू.पी.एस.के.एन.एन.एल. को क्रमशः 1893 एवं 546 सचिवालयों के निर्माण का कार्य सौपा गया। ₹ 252.57 करोड़ की धनराशि (₹ 189.38 करोड़ यू.पी.पी.सी.एल. एवं ₹ 63.19 करोड़ यू.पी.एस.के.एन.एन.एल.) का भुगतान (मार्च 2010) में सहमति पत्र पर

हस्ताक्षर किये बिना एवं निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु समय का निर्धारण किये बिना किया गया। एक ग्राम पंचायत सचिवालय के निर्माण की लागत ₹ 14.72 लाख में सेवा कर ₹ 0.52 लाख एवं सेन्टेज प्रभार ₹ 1.58 लाख (12.5 प्रतिशत की दर से) सम्मिलित थी। इस प्रकार कुल सेवा कर ₹ 12.68 करोड़ का भुगतान 2439 ग्राम पंचायत सचिवालयों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्थाओं को किया गया था यद्यपि वित्त अधिनियम 2005 के प्रस्तर 28.3—3 में सरकारी भवनों या कार्यालय अथवा जनोपयोग के लिए सिविल निर्माण कार्यों के लिए सेवा कर से मुक्त रखा गया है। कार्यदायी संस्थाओं को सेन्टेज प्रभार के तहत कुल ₹ 38.54 करोड़ का भुगतान किया गया जबकि कुछ पंचायती राज संस्थाओं ने सेन्टेज प्रभार का दावा नहीं किया था। इस प्रकार कार्यदायी संस्थाओं को भुगतानित सेवा कर ₹ 12.68 करोड़ देय नहीं था, जबकि यदि यह कार्य जिला पंचायतों को सौंपे गये होते तो ₹ 38.54 करोड़ का कार्यदायी संस्थाओं को किया गया सेन्टेज प्रभार का भुगतान परिहार्य था।

इंगित किये जाने पर (अगस्त 2010) कार्यदायी संस्थाओं (EAS) ने अवगत कराया कि सेवा कर को अब तक जमा नहीं किया गया है एवं सेवा कर सलाहकार से परामर्श के पश्चात कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्धन इकाई ने भी आश्वासन (दिसम्बर 2010) दिया कि कार्यदायी संस्थाओं को सेवा कर के रूप में भुगतानित धनराशि को भविष्य में लेन देन के समय समायोजित किया जायेगा। इस प्रकार सेवा कर के तहत हस्तान्तरित धनराशि ₹ 12.68 करोड़ देय नहीं थी तथा कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान की गयी सेन्टेज प्रभार की धनराशि ₹ 38.54 करोड़ परिहार्य थी।

2.7.5 कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ग्राम पंचायत सचिवालय के निर्माण में धीमी प्रगति के कारण ₹ 97.07 करोड़ लागत में वृद्धि।

परियोजना प्रबन्धन इकाई (पी.एम.यू.) के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2010) एवं जिला वार्षिक योजना की जांच में पाया गया कि वर्ष 2007—08 में एक ग्राम पंचायत सचिवालय की लागत ₹ 10.74 लाख थी जिसे जुलाई 2009 में बढ़ाकर ₹ 14.72 लाख किया गया। इस प्रकार 2439 ग्राम पंचायत सचिवालयों की लागत में ₹ 97.07 करोड़ की वृद्धि, नियोजन स्तर पर ही बढ़ गई थी। ग्राम पंचायतों के बिना पर्यवेक्षण के ग्राम पंचायत सचिवालयों के निर्माण हेतु (जुलाई—सितम्बर 2010) यू.पी.पी.सी.एल. को (1893 इकाई) एवं यू.पी.एस.के.एन.एन.एल (546 इकाई) का निर्माण कार्य सौंपा गया था। इस प्रकार कार्यदायी संस्थाओं द्वारा योजना के दिशा—निर्देशों की अवहेलना के कारण निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति रही, इसके अलावा 653 प्रकरणों में ₹ 96.12 करोड़ की धनराशि बिना भूमि का अधिग्रहण किये कार्यदायी संस्थाओं को हस्तान्तरित की गयी (जुलाई 2010), तथापि 77 ग्राम पंचायत सचिवालयों हेतु

₹ 11.33 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष यू.पी.एस.के.एन.एन.एल. द्वारा भूमि उपलब्ध होने पर भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।

इस प्रकार नियोजन एवं निर्माण कार्य में विलम्ब के परिणाम स्वरूप समय एवं कीमत में वृद्धि के साथ परियोजना के उद्देश्य पंचायतों को इस योग्य बनाना कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नियोजन क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जा सके, को विस्मृत किया गया।

2.7.6 उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के स्थान पर दूसरी परियोजनाओं का निर्माण करना।

जिला पंचायत, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, क्षेत्र पंचायत रमिया-बेहर जनपद खीरी एवं क्षेत्र पंचायत राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि को दूसरी परियोजनाओं के लिए बिना सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृत किए निम्न विवरणानुसार हस्तान्तरित किया गया था:-

- जिला पंचायत जौनपुर के अभिलेखों की जांच (जून 2010) में पाया गया कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा जौनपुर जिला चिकित्सालय में सोलर पावर इलेक्ट्रीफिकेशन हेतु ₹ 22.00 लाख स्वीकृत किया गया था (सितम्बर 2008) जबकि इसके स्थान पर धनराशि को सड़क निर्माण पर बिना उच्चाधिकार समिति के पूर्व स्वीकृति के अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जौनपुर ने व्यय किया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर अपर मुख्य अधिकारी ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2010)।
- जिला पंचायत, लखीमपुर-खीरी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत फूल-बेहर में नरहर बंधा से रामपुरवा तक खडंजा सड़क का निर्माण हेतु ₹ 7.00 लाख की स्वीकृति दी गयी थी। कार्यादेश जारी होने के 6 माह बाद (जनवरी 2009) अवर अभियन्ता ने सूचित किया (जुलाई 2009) कि लो.नि.वि. द्वारा पिछले वर्ष एक सड़क एवं पुलिया का निर्माण कराया गया था, जो बाढ़ में बह गया एवं क्षेत्रवासियों को वह जगह छोड़ने को मजबूर होना पड़ा तथा वहां पर खडंजा सड़क बनाया जाना संभव नहीं था। स्वीकृत सड़क के स्थान पर क्षेत्र पंचायत फूल-बेहर ने निघांसन से सरवा गांव तक दूसरी सड़क का निर्माण कराया जिस पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की पूर्व स्वीकृति के बिना ₹9.13 लाख व्यय किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखीमपुर खीरी ने अपने उत्तर में तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल 2010)। इस प्रकार कार्य का प्रस्ताव

एवं अनुमोदन सर्वेक्षण कराये बिना ही किया गया था तथा दूसरे कार्य पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की पूर्व स्वीकृति के बिना धनराशि व्यय की गयी।

- क्षेत्र पंचायत रमिया-बेहर जनपद लखीमपुर खीरी एवं क्षेत्र पंचायत, राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रत्येक संसाधन केन्द्र के निर्माण हेतु कार्य योजना के अनुसार उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने ₹ 2.80 लाख स्वीकृत किया किन्तु इसका निर्माण नहीं कराया गया। इसके स्थान पर उसी धनराशि से उच्चाधिकार प्राप्त समिति के पूर्व स्वीकृत के बिना क्षेत्र पंचायत के अनुमोदन पर एक रपटा एवं ब्लाक प्रमुख कक्ष का निर्माण कराया गया।

उक्त बिन्दु पर सम्परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर क्षेत्र पंचायत रमिया बेहर ने अवगत कराया कि (जुलाई 2010) कम्युनिटी हाल को संसाधन केन्द्र के रूप में उपयोग किया जा रहा था, जबकि क्षेत्र पंचायत राबर्टसगंज ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा स्वीकृत धनराशियों का उपयोग अन्य परियोजनाओं पर बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये किया गया था।

2.7.7 संसाधन केन्द्रों का अपूर्ण निर्माण

पंचायती राज संस्थाओं के विकेन्द्रीकृत नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए तकनीकी सहायता/समर्थन दिये जाने हेतु दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक संसाधन केन्द्र के निर्माण का प्रावधान था। नौ जिला पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 116 संसाधन केन्द्रों के निर्माण की स्वीकृति (जुलाई-सितम्बर 2008) उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रदान की गयी थी। स्वीकृत लागत ₹ 6.91 लाख में ₹ 2.80 लाख बी.आर.जी.एफ. क्षमता वृद्धि अनुदान से तथा ₹ 4.11 लाख अन्य स्रोत से व्यय सम्मिलित था। परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी मार्च 2010 की प्रगति रिपोर्ट की जांच में पाया गया कि 116 स्वीकृत संसाधन केन्द्रों में 45 संसाधन केन्द्र पूर्ण हो गये थे, 45 संसाधन केन्द्रों का कार्य प्रगति पर था तथा शेष 26 संसाधन केन्द्रों का कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ था। इस कारण प्रगति धीमी थी।

अग्रेतर जांच में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ एवं क्षेत्र पंचायत बड़हलगंज तथा बेलघाट जनपद गोरखपुर में संसाधन केन्द्र के निर्माण का कार्य प्रगति पर (जून-जुलाई 2010) था, यद्यपि परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा अपनी प्रगति रिपोर्ट (मार्च 2010) में इन्हें पूर्ण दर्शाया गया था।

उदधृत किये जाने पर नमूना जांच की गई क्षेत्र पंचायतों ने (जून-जुलाई 2010) अवगत कराया कि कार्य प्रगति पर थे, जबकि गलत रिपोर्टिंग के लिए अपर मुख्य अधिकारियों

(जिला नोडल संस्थाये) ने (अगस्त 2010) बताया कि जांच की जायेगी। इस प्रकार दिशा निर्देशों के प्रावधानों की अवहेलना की वजह से प्रत्येक क्षेत्र पंचायत को एक संसाधन केन्द्र न मिलने के परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थानों को तकनीकी सहायता/समर्थन की कमी रही।

2.8 आन्तरिक नियन्त्रण एवं अनुश्रवण

2.8.1 भौतिक एवं वित्तीय लेखा परीक्षा की विफलता

दिशा निर्देशों में प्राविधानित था कि योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में बी आर जी एफ कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक सम्प्रेक्षा वर्ष के अन्त में नियमित रूप से या तो स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों द्वारा या सनदी लेखाकारों द्वारा की जानी थी ऐसी लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन द्वितीय किस्त की धनराशि को अवमुक्त कराने के प्रस्तावके साथ प्रस्तुत किया जाना था। जिला पंचायत, हरदोई एवं 14 क्षेत्र पंचायतों¹⁶ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निर्धारित वार्षिक लेखापरीक्षा का कार्य नहीं किया गया था।

अपर मुख्य अधिकारी, हरदोई ने उत्तर में (जुलाई 2010) बताया कि सम्प्रेक्षा हेतु कार्यवाही की जा रही है एवं क्षेत्र पंचायत के खण्ड विकास अधिकारियों ने (मई-जुलाई 2010) अवगत कराया कि लेखापरीक्षा कराये जाने के लिए धनराशि का प्रावधान न होने के कारण लेखापरीक्षा नहीं करायी जा सकी।

2.8.2 समीक्षा समिति का गठन न किया जाना

प्रत्येक जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में एवं क्षेत्र पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों के प्रमुखों की एक समीक्षा समिति का गठन किया जाना था जिसे पंचायतों द्वारा कार्यों की प्रगति पर तैयार की गयी प्रणाली समीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच करना था। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं परियोजना प्रबन्धन इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि न तो प्रणाली समीक्षा प्रतिवेदन सम्बन्धित पंचायतों द्वारा तैयार किया गया और न ही जिला समीक्षा समितियों का गठन किया गया था।

उद्धृत किये जाने पर जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों ने तथ्य को (मई-जुलाई 2010) को स्वीकार किया गया जबकि परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा कोई उत्तर (जुलाई 2010) नहीं दिया गया।

¹⁶ रामिया बेहर, फूल बेहर, भदूलगंज बेलघाट, मछलीशहर, रामपुर, राबटसगंज, चोपन, हरपालपुर सन्डीला, परसन्दी, खैराबाद एवं जमुनाहा।

2.8.3 गुणवत्ता अनुश्रवण पद्धति को लागू न किया जाना

दिशा निर्देशों में प्राविधान किया गया था कि योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए गुणवत्ता अनुश्रवण पद्धति को स्थापित किया जाय एवं उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच.पी.सी.) को भी नियमित रूप से अनुश्रवण पद्धति के कार्यों की समीक्षा करना था ताकि बी.आर.जी.एफ. योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। यद्यपि सरकार ने (जुलाई 2010) अनुश्रवण पद्धति को लागू नहीं किया था अतः उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुश्रवण पद्धति की समीक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता है।

इंगित किये जाने पर नमूना जांच की जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया।

2.8.4 सामाजिक लेखापरीक्षा के क्रियान्वयन में विफलता

सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम एवं वार्ड सभा द्वारा परियोजनाओं के सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु दिशा निर्देश निर्गत करना था इसमें उसी प्रक्रिया का पालन किया जाना था जो मनरेगा के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया गया है। जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों की नमूना जांच में पाया गया कि कोई सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं कराया जा रहा था। परियोजना निदेशक (पी.एम.यू.) ने अवगत (अगस्त 2010) कराया कि सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए कोई दिशा निर्देश निर्गत नहीं किये गये हैं। इस कारण दिशा निर्देश के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षा किये जाने के प्रावधान का पालन नहीं किया गया था।

ऐसे लेखापरीक्षा के क्रियान्वयन की विफलता के कारण उच्चाधिकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजना की धनराशि का समुचित उपयोग एवं कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

2.9 निष्कर्ष

निष्पादन सम्प्रेक्षा ने उद्घाटित किया कि सरकार समय पर भावी योजना नहीं बना सकी जिसके कारण जिला नियोजन समितियों के गठन में विलम्ब हुआ। योजना के क्रियान्वयन के लिए मूल ढांचागत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में विलम्ब के कारण तथा एन.सी.बी.एफ. अनुदान के दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत क्षमता संवर्धन योजना को बनाने में सरकार की असमर्थता के कारण ₹ 1268.24 करोड़ की अनुदान की धनराशि वर्ष 2006 से 2010 तक की अवधि में कुल आवंटित धनराशि ₹ 2418.55 करोड़ के विरुद्ध प्राप्त नहीं की जा सकी। नौ

जनपदों की नमूना जांच में पाया गया कि सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को सीधे पंचायतों के खातों में 15 दिन के अन्दर हस्तान्तरित न करने से ₹ 5.84 करोड़ ब्याज के दायित्व का सृजन किया गया। शासन द्वारा जनपद के अन्दर एवं पंचायतों के मध्य धनराशि को हस्तान्तरण के लिए योजना के मानक सिद्धान्त न अपनाये जाने की वजह से स्थानीय निकाय क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों का ₹ 103.75 करोड़ का अंश जिला पंचायतों को अधिक हस्तान्तरित किया गया। शासन द्वारा न्यूनतम तुलनात्मक दरों के लिए प्रयास किये बिना कार्यदायी संस्थाओं को ग्राम सचिवालय निर्माण के लिए नामित किया था। इसके लिए ₹ 12.68 करोड़ सेवा कर जो देय नहीं था का भुगतान किया गया तथा सेन्टेज प्रभार की मद में ₹ 38.54 करोड़ परिहार्य व्यय किया गया। योजना के प्राविधान एवं निर्देशों के अनुसार प्रतिवर्ष नियमित भौतिक एवं वित्तीय लेखापरीक्षा न किया जाना, समीक्षा समितियों का गठन जनपदों में न किया जाना एवं गुणवत्ताअनुश्रवण पद्धति तथा सामाजिक लेखापरीक्षा के प्रावधान का पालन नहीं किये जाने के कारण प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

2.10 संस्तुतियां

- प्रत्येक बी.आर.जी.एफ. जनपद के लिए एकीकृत, सहभागी भावी योजनायें बनाई जायें एवं जिला योजनाओं के अनुमोदन एवं क्रियान्वयन की समय सीमा का निर्धारण किया जाये व इसका पालन किया जाये तथा परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाय।
- भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि को प्राप्ति से पन्द्रह दिन के अन्दर सम्बन्धित पंचायतों के खातों में सीधे हस्तान्तरित कर दिया जाय।
- धनराशि को स्थानीय निकाय एवं पंचायतों के मध्य तथा पंचायतों के बीचमानक सूत्र के अनुसार बांटना चाहिए।
- योजना के लिए प्रभावी आन्तरिक नियन्त्रण एवं अनुश्रवण पद्धति का प्रत्येक स्तर पर पालन किया जाना चाहिए एवं मूल्यांकन पद्धति को समाविष्ट किया जाना चाहिए।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित (नवम्बर 2010) किया गया था उत्तर प्रतीक्षित (मई 2011) था।

अध्याय—III

लेन देनों की लेखा परीक्षा

3.1 रायल्टी का अनियमित भुगतान

शासकीय¹ आदेशों की उपेक्षा के कारण ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण में मिट्टी के उपभोग पर रायल्टी के माध्यम से ₹ 4.36 लाख का अनियमित भुगतान।

अनुदान की धनराशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बारहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण में उपयोग की गई मिट्टी पर रायल्टी के भुगतान पर शासनादेश¹⁷ द्वारा रोक लगा दी गयी थी।

जिला पंचायत, श्रावस्ती के अभिलेखों (नवम्बर 2009) की नमूना जाँच में यह पाया गया कि सरकार ने बारहवां वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत क्रमशः 49 एवं 18 ग्रामीण सम्पर्क मार्ग वर्ष 2007–08 में स्वीकृत किया गया था। जिसकी कुल प्राक्कलन लागत ₹ 2.30 करोड़ थी। प्राक्कलन में ₹ 4.36 लाख की रायल्टी के भुगतान का प्रावधान इन सम्पर्क मार्गों के निर्माण में मिट्टी के उपयोग हेतु किया गया था। रायल्टी सम्मिलित करते हुए प्राक्कलन स्वीकृत करना अनियमित था, क्योंकि उक्तशासनादेश ने इसे प्रतिबन्धित किया था। सड़कों का निर्माण सम्बन्धित वर्षों के स्वीकृति आदेशों के तहत, उन्हीं वर्षों में पूर्ण कराया गया, जिस पर ₹ 4.36 लाख का रायल्टी के मद में अनियमित भुगतान हुआ।

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, श्रावस्ती ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2009) कि जिला अधिकारी के आदेशानुसार रायल्टी का भुगतान किया गया। यह उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि सड़क निर्माण में सरकारी आदेशों कापालन नहीं किया गया, फलस्वरूप ₹ 4.36 लाख का अनियमित भुगतान हुआ जिसे अन्य विकास कार्यों में उपयोग किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शासकीय आदेशों का अतिक्रमण करने के लिए सक्षम नहीं थे। जिला स्तर पर शासकीय आदेशों का समय समय पर समुचित संप्रेषण और इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इस प्रकरण को शासन के संज्ञान में (मार्च 2011) लाया गया था। जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2011)।

¹⁷ संख्या 1100/33-प्रकोष्ठ/2006-113/05 दिनांक 17 जनवरी, 2006

3.2 अधोमानक कार्यों पर निष्फल व्यय

सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों की उपेक्षा के कारण अधोमानक कार्य पर ₹ 7.01 लाख का निष्फल व्यय

जिला पंचायत, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों/मानक के अनुसार सड़क निर्माण कराता है। विशिष्टियों¹⁸ के अनुसार वाटर बाउन्ड मेकेडम के ऊपर एक विटुमिनस सतह की प्रथम कोटिंग करने के पश्चात प्रीमिक्स कार्पेटिंग (प्री.सी.) और सील कोट कराना चाहिए।

जिला पंचायत, ज्योतिबाफूलेनगर के अभिलेखों की जाँच में (जुलाई 2010) यह ज्ञात हुआ कि करमालीपुर से बसेरवा पेंटेड सड़क का निर्माण (1.92 कि.मी. लम्बी 3 मीटर चौड़ी) वर्ष 2009-10 में ₹ 30.03 लाख की लागत में स्वीकृत थी। सड़क पर किया गया व्यय बारहवों वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से किया जाना था। यद्यपि इस प्राक्कलन में वाटर बाउन्ड मेकेडम के ऊपर सील कोट और प्रीमिक्स कार्पेटिंग के पूर्व प्राइम कोट के लिए कोई प्रावधान नहीं था जो निर्धारित विशिष्टियों के विपरीत था।

कार्य का निष्पादन वर्ष 2009-10 में किया गया और पी.सी. और सील कोट पर ₹ 7.01 लाख व्यय किया गया। इस प्रकार विशिष्टियों के विपरीत पेंटेड सड़क का निर्माण कराने से कार्य अधोमानक हुआ एवं लम्बे समय तक सड़क का बने रहना संदिग्ध था। अतः पी0सी0 और सील कोट पर किया गया ₹ 7.01 लाख का व्यय निष्फल हुआ। लेखा परीक्षा द्वारा इस विषय पर इंगित किये जाने पर, अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि प्राइम कोट किया गया जबकि प्राक्कलन में इसका प्राविधान नहीं था और ठेकेदार को इन पर कोई भुगतान नहीं किया गया।

उत्तर संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि प्राइमकोट के साथ कार्य का निष्पादन बिना प्राक्कलन में प्रावधान और ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जाना, सिर्फ काल्पनिक है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों का सड़कों के निर्माण पर अनुपालन जिला पंचायत द्वारा सुनिश्चित करना चाहिए और कार्यदायी संस्था द्वारा अभिलेखों का रखरखाव करना चाहिए।

प्रकरण शासन को (नवम्बर 2010) में सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्रतिक्रिया (मई 2011)।

¹⁸ लोक निर्माण विभाग प्रपत्र सं 3583 दिनांक 13/06/2007

3.3 परिहार्य व्यय

ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण पर निर्धारित विशिष्टियों का पालन न किए जाने के कारण ₹ 17.26 लाख का परिहार्य व्यय।

लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिए निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार टैक कोट/प्राइम कोट आन वाटर वाउन्ड मैकेडम/टापकोट के पश्चात निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक तरीके को अपनाया जा सकता है।

सतह लेपन { पेंटिंग I (P1) & पेन्टिंग 2 (P2)}

प्रीमिक्स कारपेट, विद सीलकोट (पी.सी. एवं एस.सी.)

जिला पंचायत कुशीनगर और मिर्जापुर के अभिलेखों के परीक्षण करने पर यह पाया गया कि (जुलाई 2009 एवं जनवरी 2010 के मध्य) जिला पंचायत कुशीनगर में तीन ग्रामीण सम्पर्क मार्गों और जिला पंचायत मिर्जापुर में छः ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिए सम्पूर्ण आंकलित लागत क्रमशः ₹121.00 लाख एवं ₹ 51.00 लाख बारहवों वित्त आयोग से वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। जबकि समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों का उल्लंघन करते हुए मार्च 2008 एवं मार्च 2010 के दौरान ग्रामीण सम्पर्क मार्गों पर क्रमशः ₹ 7.87 लाख एवं ₹ 9.39 लाख अतिरिक्त/अधिक व्यय किया गया। उत्तर में अपर मुख्य अधिकारी कुशीनगर ने अवगत कराया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी परिपत्र से अनभिज्ञ थे, जबकि अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत मिर्जापुर ने यह अवगत कराया कि सड़क का निर्माण स्थलीय आवश्यकतानुसार किया गया। उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि वास्तविक स्थिति यह कि निर्धारित विशिष्टियों के मानकों का पालन न करने से परिहार्य व्यय ₹17.26 लाख मार्च 2008 से मार्च 2010 के दौरान किया गया।

ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के निर्माण में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों को जिला पंचायत द्वारा अनुश्रवण एवं अनुपालन करना चाहिए।

इनप्रकरणों को शासन को (जनवरी से दिसम्बर 2010) सन्दर्भित किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2011)।

3.4 राजस्व की हानि

आहरण/वितरण अधिकारी द्वारा बिना आयकर की कटौती किये ठेकेदारों को भुगतान करने से ₹ 1.20 लाख की राजस्व की हानि

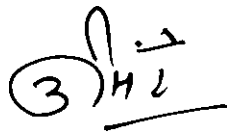
आयकर नियमों के अन्तर्गत आहरण-वितरण अधिकारी को ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय उनके देयकों से 2.24% (0.24% प्रभार सम्मिलित करते हुये) की दर से आयकर की कटौती करनी चाहिए। इस कटौती के न करने पर, उस व्यक्ति को आयकर राशि के बराबर राशि दण्ड स्वरूप भुगतान करना है। क्षेत्र पंचायत, बधौली और खलिलाबाद

राशि के बराबर राशि दण्ड स्वरूप भुगतान करना है। क्षेत्र पंचायत, बधौली और खलिलाबाद एवं सन्था, जिला सन्त कबीर नगर के अभिलेखों के जांच करने पर (जनवरी-फरवरी 2010) पाया गया कि ठेकेदारों को ₹ 53.70 लाख,¹⁹ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्रियों के आपूर्ति हेतु भुगतान किया गया, परन्तु ठेकेदार के देयको से आयकर की कटौती @ 2.24% की दर से ₹ 1.20 लाख भुगतानित धनराशि से काटा नहीं गया था, फलस्वरूप इतने राजस्व की हानि हुई। उत्तर में उन क्षेत्र पंचायतों के खण्ड विकास अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में आयकर की कटौती की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा आयकर की कटौती न किया जाना नियमों का उल्लंघन था। इस प्रकार ठेकेदार से देयक के भुगतान के समय, स्रोत पर आयकर कटौती न किये जाने से ₹ 1.20 लाख के राजस्व की हानि हुई (परिशिष्ट 3.1) इसके अतिरिक्त उपर्युक्त धनराशि के बराबर अर्थदण्ड, अभी तक आहरण-वितरण अधिकारियों के ऊपर संगत नियमों के तहत नहीं लगाया गया था।

आहरण वितरण अधिकारी को भुगतान पूर्व आयकर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

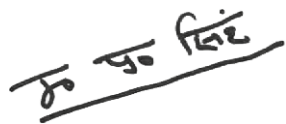
प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया था (अक्टूबर 2010)। उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2011)।

इलाहाबाद
दिनांक


यू.पी. सिंह सिसोदिया
उपमहालेखाकार
स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

इलाहाबाद
दिनांक


मुकेश पी. सिंह
प्रधान महालेखाकार
(सिविल आडिट) उत्तर प्रदेश

¹⁹ क्षेत्र पंचायत बधौली ₹ 5.14 लाख, क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद ₹ 16.76 लाख, क्षेत्र पंचायत सान्था ₹ 31.80 लाख।

परिशिष्ट-1.1
(सन्दर्भ-प्रस्तर संख्या 1.5.4 पृष्ठ संख्या-8)
जिला पंचायत में कर संग्रह में अवशेष (2008-09)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला पंचायत का नाम	पूर्व शेष	चालू वर्ष की मांग	योग	वर्ष के दौरान वसूली	शेष 31.03.2009
1	जौनपुर	46.22	69.10	115.32	52.16	63.16
2	बहराईच	169.90	124.07	293.97	122.74	171.23
3	कानपुर नगर	721.23	395.40	1,116.63	621.72	494.91
4	बागपत	215.91	101.05	316.96	58.14	258.82
5	रामपुर	0	69.45	69.45	57.55	11.90
6	आगरा	33.94	152.97	186.91	100.63	86.28
7	महोबा	0	88.600	88.60	15.30	73.30
8	बदायूं	0	1.58	1.58	0.58	1.00
9	फर्रुखाबाद	145.56	103.36	248.92	76.28	172.64
10	बांदा	0	94.00	94.00	53.53	40.47
11	फतेहपुर	92.80	167.17	259.97	124.31	135.66
12	रायबरेली	195.21	58.43	253.64	72.20	181.44
13	बरैली	207.05	218.23	425.28	109.32	315.96
14	ज्योतीबाफूलेनगर	123.17	84.15	207.32	166.01	41.31
15	सुलतानपुर	59.07	90.95	150.02	71.10	78.92
16	मिर्जापुर	167.65	114.98	282.63	91.73	190.90
17	बलिया	56.13	126.84	182.40	129.07	53.46
18	आजमगढ़	67.16	149.84	217.00	141.29	75.71
19	लखनऊ	186.89	4.25	191.14	134.66	56.48
20	मेरठ	230.60	200.59	431.19	69.80	361.39
21	इलाहाबाद	133.12	256.80	389.92	250.59	139.33
22	भदोही	50.07	46.80	96.87	40.69	56.18
23	उरई, जालौन	15.60	108.86	124.46	120.57	3.89
24	मुजफ्फरनगर	323.52	227.43	550.95	224.03	326.92
25	सोनभद्र	157.67	547.36	705.03	557.50	147.53
26	प्रतापगढ़	90.67	121.53	212.20	129.24	82.96
27	श्रावस्ती	26.00	71.71	97.71	43.34	54.37
28	चन्दौली	50.10	69.50	119.60	32.35	87.25
29	अम्बेडकर नगर	51.30	14.90	66.20	58.85	7.35
	योग	3,616.54	3,879.46	7,496.00	3,725.28	3,770.72

स्रोत: (लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन 2009-10)

परिशिष्ट-1.2
(संदर्भ- प्रस्तर संख्या 1.9, पृष्ठ संख्या-10)
रोकड़ अवशेष का मिलान न किया जाना

(₹ लाख में)

क. सं.	जिला पंचायत का नाम	सम्प्रेक्षा अवधि	31.03.2009 को अवशेष		अन्तर
			रोकड़ बही के अनुसार	पास बुक के अनुसार	
जिला पंचायतों में रोकड़ अवशेषों का मिलान न किया जाना					
1	जौनपुर	2008—09	1,081.44	1,197.08	115.64
2	गाजीपुर	2008—09	456.35	434.44	21.91
3	मिर्जापुर	2008—09	729.04	873.06	144.02
4	चन्दौली	2008—09	473.38	557.90	84.52
5	बागपत	2008—09	213.61	241.00	27.39
6	जालौन (उरई)	2008—09	691.55	584.10	107.45
7	बलरामपुर	2008—09	892.63	959.00	66.37
8	महामाया नगर (हाथरस)	2008—09	224.96	330.40	105.44
9	बलिया	2008—09	409.21	284.77	124.44
10	बांदा	2008—09	1,991.01	2,165.46	174.45
				योग	971.63
क्षेत्र पंचायतों में रोकड़ अवशेषों का मिलान न किया जाना					
1	हुजूरपुर	2008—09	78.59	80.53	1.94
2	मान्दा	2008—09	65.79	66.51	0.72
3	कालाकंकर	2008—09	68.35	62.66	5.69
4	मन्धाता	2008—09	105.89	110.27	4.38
5	हलदौर	2008—09	8.25	8.44	0.19
6	शमली	2008—09	2.48	8.38	5.90
7	धानुपुर	2008—09	12.06	20.38	8.30
8	विधानु	2008—09	46.07	52.08	6.01
9	मल	2008—09	60.07	117.56	57.49
10	चाजलत	2008—09	51.78	56.03	4.25
11	कल्यानपुर	2008—09	42.13	42.99	0.86
12	खुतार	2008—09	7.94	8.79	0.85
13	ननौता	2008—09	9.69	13.87	4.18
14	कुरारा	2008—09	24.77	28.41	3.64
15	काशी विद्यापीठ	2008—09	9.06	8.83	0.23
16	खेखारा	2008—09	23.40	23.83	0.43
17	केटेहरा	2008—09	46.40	56.83	10.43
				योग	115.49

स्रोत: (लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2008-09)

परिशिष्ट-2.1
(संदर्भ- प्रस्तर संख्या 2.6.2, पृष्ठ संख्या-21)
जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में स्वीकृत
एवं अवमुक्त धनराशि का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिले का नाम	जिला पंचायतें			क्षेत्र पंचायतें			ग्राम पंचायतें		
		स्वीकृत	अवमुक्त	अधिक्य(+) / कमी(-) अवमुक्त	स्वीकृत	अवमुक्त	अधिक्य(+) / कमी(-) अवमुक्त	स्वीकृत	अवमुक्त	अधिक्य(+) / कमी(-) अवमुक्त
1	अम्बेडकर नगर	1.00	2.41	1.41	3.51	3.86	0.35	0.50	0.11	(-) 0.39
2	आजमगढ़	3.44	12.26	8.82	12.05	5.87	(-) 6.18	1.72	0.00	(-) 1.72
3	बदायूं	3.27	3.21	(-) 0.06	11.44	15.65	4.21	1.63	0.65	(-) 0.98
4	बहराइच	2.93	7.47	4.54	10.25	5.01	(-) 5.24	1.46	0.00	(-) 1.46
5	बलरामपुर	2.57	5.14	2.57	8.99	5.73	(-) 3.26	1.28	0.00	(-) 1.28
6	बांदा	1.82	5.29	3.47	6.36	3.94	(-) 2.42	0.91	0.00	(-) 0.91
7	बाराबंकी	2.19	6.08	3.89	7.65	3.46	(-) 4.19	1.09	0.00	(-) 1.09
8	बस्ती	2.65	5.23	2.58	9.28	9.15	(-) 0.13	1.33	1.33	0.00
9	चन्दौली	2.47	4.50	2.03	8.64	6.52	(-) 2.12	1.23	0.00	(-) 1.23
10	चित्रकूट	1.77	8.26	6.49	6.19	2.75	(-) 3.44	0.88	0.00	(-) 0.88
11	एटा	3.09	5.38	2.29	10.80	11.90	(-) 1.10	1.54	0.58	(-) 0.96
12	फर्रुखाबाद	2.40	1.49	(-) 0.91	8.41	11.29	2.88	1.20	0.00	(-) 1.20
13	फतेहपुर	2.88	5.72	2.84	10.08	8.10	(-) 1.98	1.44	1.65	0.21
14	गोंडा	3.03	6.06	3.03	10.61	9.34	(-) 1.27	1.52	1.21	(-) 0.31
15	गोरखपुर	3.32	6.25	2.93	11.62	13.02	1.40	1.66	0.90	(-) 0.76
16	हमीरपुर	2.44	3.07	0.63	8.53	12.16	3.63	1.22	0.00	(-) 1.22
17	हरदोई	2.05	1.72	(-) 0.33	7.17	7.84	0.67	1.02	0.00	(-) 1.02
18	जालौन	1.85	2.62	0.77	6.49	8.97	2.48	0.93	0.00	(-) 0.93
19	जौनपुर	3.45	15.06	11.61	12.06	5.61	(-) 6.45	1.72	0.25	(-) 1.47
20	कोशाम्बी	2.28	3.85	1.57	7.99	8.41	0.42	1.14	0.28	(-) 0.86
21	कुशीनगर	2.96	2.96	0.00	10.34	12.56	2.22	1.48	1.65	0.17
22	लखीमपुर खीरी	3.59	7.28	3.69	12.56	10.65	(-) 1.91	1.79	0.22	(-) 1.57
23	ललितपुर	2.22	9.32	7.10	7.77	1.07	(-) 6.70	1.11	3.07	1.96
24	महाराजगंज	2.70	11.10	8.40	9.45	5.44	(-) 4.01	1.35	0.98	(-) 0.37
25	महोबा	1.53	3.87	2.34	5.36	5.24	(-) 0.12	0.77	0.44	(-) 0.33
26	मिर्जापुर	2.85	5.63	2.78	9.97	11.44	1.47	1.42	0.59	(-) 0.83
27	प्रतापगढ़	2.99	2.73	(-) 0.26	10.45	15.89	5.44	1.49	0.00	(-) 1.49
28	रायबरेली	3.13	0.00	(-) 3.13	10.97	17.95	6.98	1.57	0.00	(-) 1.57
29	संत कबीर नगर	2.29	3.97	1.68	8.00	8.22	0.22	1.14	0.53	(-) 0.61
30	श्रावस्ती	2.29	4.16	1.87	8.03	6.55	(-) 1.48	1.15	0.00	(-) 1.15
31	सिद्धार्थ नगर	2.64	6.78	4.14	9.25	8.24	(-) 1.01	1.32	0.00	(-) 1.32
32	सीतापुर	3.53	5.78	2.25	12.36	11.66	(-) 0.70	1.77	0.90	(-) 0.87
33	सोनभद्र	2.86	12.51	9.65	10.01	5.37	(-) 4.64	1.43	0.00	(-) 1.43
34	उन्नाव	3.07	6.14	3.07	10.74	5.56	(-) 5.18	1.53	1.33	(-) 0.20
		89.55	193.30	103.75	313.38	284.42	(-) 28.96	44.74	16.67	(-) 28.07

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ- प्रस्तर संख्या 2.7.1, पृष्ठ संख्या-23)

विलम्ब (15 दिन से अधिक) एवं दण्डात्मक ब्याज की धनराशि @11.75% प्रति वर्ष

(₹ लाख में)

जिले का नाम	2008-09					2009-10					दण्डात्मक ब्याज की कुल धनराशि
	धनराशि (₹ लाख में)	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अवमुक्त की तिथि	पंचायती राज संस्थाओं/ कार्यकारी संस्थाओं को अवमुक्त की तिथि	विलम्ब दिनों में	दण्डात्मक ब्याज की धनराशि @11.75%	धनराशि (₹ लाख में)	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अवमुक्त की तिथि	पंचायती राज संस्थाओं/ कार्यकारी संस्थाओं को अवमुक्त की तिथि	विलम्ब दिनों में	दण्डात्मक ब्याज की धनराशि @11.75%	
लखीमपुर खीरी	2018.7	21.10.2008	29.12.2008	54	35.09	1,654	5.11.2009	30.1.2010	71	37.80	72.90
					0	589	26.2.2010	31.3.2010	18	3.413	3.41
गोरखपुर	1867	10.09.2008	11.12.2008	77	46.28	1,435	22.09.2010	24.11.2009	48	22.17	68.45
					0	640	25.2.2010	25.3.2010	13	2.68	2.68
सीतापुर	1986	21.10.2008	11.12.2008	36	23.02	1,498	18.12.2009	23.3.2010	80	38.58	61.59
					0	709	25.3.2010	31.3.2010	0	0	0
कुशीनगर	1662	10.09.2008	11.12.2008	77	41.20	1,434	18.9.2009	24.11.2009	52	24.00	65.20
					0	413	25.2.2010	25.3.2010	13	1.73	1.73
जौनपुर	1938	19.11.2008	30.1.2008	57	35.56	1,634	21.10.2009	24.11.2009	19	9.99	45.56
					0	520	5.3.2010	31.3.2010	11	1.84	1.84
प्रतापगढ़	1679	5.11.2008	30.1.2008	71	38.38	1,490	15.9.2009	24.11.2009	55	26.38	64.76
					0	376	25.2.2010	25.3.2010	13	1.57	1.57
हरदोई	1954	21.10.2008	11.12.2008	36	22.64	1,281	5.11.2009	31.3.2010	131	54.02	76.67
श्रावस्ती	1290	10.09.2008	11.12.2008	77	31.98	1,029	6.10.2009	24.11.2009	34	11.26	43.24
					0	405	26.2.2010	25.3.2010	12	1.56	1.56
सोनभद्र	1608	9.9.2008	11.12.2008	78	40.37	1,367	21.10.2009	13.1.2010	69	30.36	70.74
					0	420	26.2.2010	31.3.2010	18	2.43	2.43
योग					314.52					269.82	584.34

परिशिष्ट-3.1
(संदर्भ- प्रस्तर संख्या 3.4, पृष्ठ संख्या-35)
आपूर्तिकर्ताओं को बिना आयकर कटौती के भुगतान का विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र. सं.	यूनिट का नाम	कार्य का नाम	भुगतान का उद्देश्य	बिना आयकर कटौती के नगद भुगतान (₹)	आयकर की कटौती योग्य धनराशि @2-24%
1	क्षेत्र पंचायत बघौली जिला संत कबीर नगर	भोजपुर गोडाउन में पुलिया निर्माण कार्य	सामग्री आपूर्ति	1,48,037	3,316
2	क्षेत्र पंचायत बघौली जिला संत कबीर नगर	ग्राम भैनसाथ में खडंजा निर्माण कार्य	सामग्री आपूर्ति	97,310	2,180
3	क्षेत्र पंचायत बघौली जिला संत कबीर नगर	शहजनवा मार्ग में ईंट एवं मिट्टी कार्य	सामग्री आपूर्ति	1,11,000	2,486
4	क्षेत्र पंचायत बघौली जिला संत कबीर नगर	सिहोरवा से सिकोहरवा तक ईंट एवं मिट्टी कार्य	सामग्री आपूर्ति	1,57,479	3,528
5	क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर	डिहुलिया में सी.सी. रोड निर्माण कार्य	सामग्री आपूर्ति	3,09,059	6,923
6	क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर	ग्राम रुकमा में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य	सामग्री आपूर्ति	1,24,357	2,786
7	क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर	पयालपुर में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य	सामग्री आपूर्ति	1,03,615	2,321
8	क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर	शिवसरा में नाली निर्माण कार्य	सामग्री आपूर्ति	2,48,633	5,569
9	क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर	दुधारा में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य	सामग्री आपूर्ति	2,03,172	4,551
10	क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर	जजगैवा में आर.सी.सी. रस्लैब खडंजा निर्माण कार्य	सामग्री आपूर्ति	2,01,373	4,511
11	क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर	बिसरापुर में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य	सामग्री आपूर्ति	1,53,634	3,441
12	क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर	उरधवा में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य	सामग्री आपूर्ति	1,82,252	4,082
13	क्षेत्र पंचायत खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर	उमरी डिहुलिया मार्ग में खडंजा निर्माण कार्य	सामग्री आपूर्ति	1,49,944	3,359
14	क्षेत्र पंचायत सांथा जिला संत कबीर नगर	फुलवरिया बनौली मार्ग में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य	सामग्री आपूर्ति	3,72,225	8,338
15	क्षेत्र पंचायत सांथा जिला संत कबीर नगर	प्रतापपुर मार्ग में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य	सामग्री आपूर्ति	2,90,634	6,510
16	क्षेत्र पंचायत सांथा जिला संत कबीर नगर	राजडीहा मार्ग में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य	सामग्री आपूर्ति	1,71,079	3,832
17	क्षेत्र पंचायत सांथा जिला संत कबीर नगर	हरैया मार्ग में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य	सामग्री आपूर्ति	2,71,014	6,071
18	क्षेत्र पंचायत सांथा जिला संत कबीर नगर	खजुरी से पखापार में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य	सामग्री आपूर्ति	6,61,319	14,814
19	क्षेत्र पंचायत सांथा जिला संत कबीर नगर	रसूलपुर में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य	सामग्री आपूर्ति	3,15,135	7,059
20	क्षेत्र पंचायत सांथा जिला संत कबीर नगर	खजुरी कोक से खजुरी मार्ग में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य	सामग्री आपूर्ति	3,71,078	8,312
21	क्षेत्र पंचायत सांथा जिला संत कबीर नगर	हाकिमपुर रोड में आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य	सामग्री आपूर्ति	3,92,944	8,802
22	क्षेत्र पंचायत सांथा जिला संत कबीर नगर	परगदवा से ईदगाह तक आर.सी.सी. पुलिया निर्माण कार्य	सामग्री आपूर्ति	3,34,455	7,492
योग				53,69,748	1,20,282

